राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 11 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-284 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगी सरकार

■ राज्यपाल ने कहा: सूखा-भूखा मत समझो

एजेंसी

जयपुर। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर राजस्थान में एक लाख करोड़ का निवेश हुआ। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आज हो रहे कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि- हम प्रवासी राजस्थानियों से आपसे निवेदन करते हैं कि आप राजस्थान में भी काम करें। यहां 2 साल में सब बदल गया है। उन्होंने 14 नए राजस्थान चैप्टर की भी घोषणा की। वहीं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राजस्थानियों से राजस्थान का ब्रांड एंबेसडर बनने और यहां इंवेस्टमेंट लाने की अपील की। बुधवार सुबह 10.30 बजे पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल प्रवासी राजस्थानी दिवस की घोषणा की थी। पहले राजस्थानी दिवस पर आज राजस्थान के बैकग्राउंड वाले दुनिया के बड़े बिजनेसमैन को सरकार ने इनवाइट किया है। इनमें वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, वेलस्पन ग्रुप की दीपाली गोयनका सहित कई बिजनेसमैन शामिल हैं।

दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया

■ पीएम मोदी बोले: दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा, कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें पहले ही लिस्ट में

एजेंसी

नई दिल्ली। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची जारी की। इसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा, 'दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है।' भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छाऊ नृत्य भी शामिल हैं। ये फैसला उस समय आया है, जब दिल्ली में वठएरउड की इंटर-गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटैन्जिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक की मेजबानी कर रही है। यह 8 से 13 दिसंबर तक चलेगी। इसी मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत तरह से पेश किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने पर बधाई देते हुए लिखा, 'भारत और दुनियाभर के लोग उत्साहित हैं। हमारे लिए दिवाली, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और भी वृद्धि होगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहें। यूनेस्को की यह लिस्ट दुनिया की ऐसी सांस्कृतिक और पारंपरिक चीजों को शामिल करती है, जिन्हें छू नहीं सकते लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसे अमूर्त विश्व धरोहर भी कहते हैं। इसका मकसद है कि ये सांस्कृतिक धरोहरें सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचें। फिलहाल, भारत की 15 धरोहरें पहले से अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में जगह बना चुकी हैं। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छऊ नृत्य भी शामिल हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार अलग से दिवाली मनाएगी।

लूथरा बंधुओं को क्यों नहीं मिली अंतरिम राहत?

■ आज होगी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई

एजेंसी

नई दिल्ली। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में नाकाम रहे। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी। अतरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने दोनों भाइयों द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर गोवा सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख गुरुवार तय की।भाइयों ने चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी मांगी है। थाइलैंड भाग चुके लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम याचिका में खुद पीड़ित बताया है। दावा किया कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान आरोपी सौरभ लूथरा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए आरोपी सौरभ लूथरा की सेहत की स्थिति बताई, जिसे मिर्गी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी क्लब के मालिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ लाइसेंसधारी हैं, जो वैध परमिशन के साथ काम कर रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट बोला: इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया

4 हजार रुपये का टिकट 30 हजार रुपये तक कैसे पहुंचा, आपने ही ऐसे हालात बनने दिए

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी, तब सरकार ने क्या किया। कैसे फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4-5 हजार रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए तक कैसे पहुंच गईं। अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया। आपने क्या कार्रवाई की? आपने ही स्थिति को इस हाल तक पहुंचने दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिविजन बेंच जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई या जो एयरपोर्ट पर फंसे उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं

है, बल्कि इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न पैदा हो। इधर, DGCA (नागरिक उड्डयन नियामक) ने इंडिगो के उएड पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे समन भेजकर बुलाया है। हाईकोर्ट: सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। क्या आपने आज अखबार पढ़ा। याचिकाकर्ता: फ्लाइट रद्द होने की संख्या कम हुई है। हाईकोर्ट: अब आप क्या चाहते हैं। कार्रवाई कर रही है। एएसजी चेतन शर्मा (सरकार की ओर से): सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। किराए पर कैप लगाया गया है।। हाईकोर्ट: यात्रियों के साथ एयरलाइन कर्मचारियों का व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। पायलट के काम के घंटे की गाइडलाइन समय पर क्यों लागू नहीं की गई। एएसजी: फेयर कैपिंग बहुत सख्त तरीके से की गई। कोर्ट: यह कार्रवाई 4-5 दिन बाद हुई। टिकट जो 4-5 हजार रुपये में उपलब्ध था, उसके दाम 30,000 रुपये तक क्यों बढ़ गए? कोर्ट: यह सिर्फ फंसे हुए यात्रियों का मामला नहीं है, आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। इंडिगो संकट को लेकर अब DGCA (नागरिक उड्डयन नियामक) भी केंद्र सरकार की जांच के रडार पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, बल्कि DGCA के कामकाज की भी जांच होगी। मंत्री ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इंडिगो का यह बड़ा फेलियर सामान्य गलती नहीं लगता, बल्कि इसमें जानबूझकर हुई लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार यह जांच कर रही है कि आखिर ऐसा संकट उसी समय क्यों आया और ऑपरेशंस होने के बावजूद हालात कैसे बिगड़े। उएड को हटाने के सवाल पर नायडू ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जरूर हटाया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, वह जरूर होगी। नायडू ने ये भी बताया कि मैं पिछले 7 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहा हूं और मुश्किल से सो पाया हूं, क्योंकि फोकस सिर्फ यात्रियों की परेशानी दूर करने पर है।

एमपी में पुलिस वैन-कंटेनर की भिड़ंत, 4 जवानों की मौत

■ गाड़ी काटकर शव निकाले, नक्सल ऑपरेशन के लिए गए थे

एजेंसी

; पुलिस का डॉग सुरक्षित

सागर। नेशनल हाईवे-44 पर बांदरी के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस के वाहन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस वाहन में सवार 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं, टीम में शामिल डॉग सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड बालाघाट में ड्यूटी पर तैनात था। पुलिसकर्मी नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हुए थे। वहां से वे बीडी-डीएस वाहन (क्रमांक MP 03 A 4883) में सवार होकर वापस मुरैना लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास झिंझनी घाटी पर सामने से आ रहे कंटेनर से पुलिस वाहन की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉग मास्टर समेत चार जवानों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक, NH- 44 पर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण से बांदरी के पास हाईवे का ट्रैफिक वन वे हो गया है। इसी के चलते आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। तीन पुलिसकर्मी भिंड, एक मुरैना का था-1. आरक्षक प्रद्युम्न दीक्षित, फूफ, भिंड, 2. अनिल कौरव, टेकोन गांव, भिंड, 3. विनोद शर्मा, पुलिस लाइन, भिंड, 4. परिमल सिंह तोमर, नखती अंबाह, मुरैना। अंतिम संस्कार भिंड में ही होगा। शवों को रात तक सागर से पहले मुरैना लाया जाएगा।

पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में बम की धमकी

एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित एक निजी स्कूल में बुधवार सुबह बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के एक अधिकारी के अनुसार, धमकी भरा कॉल सुबह करीब 10:40 बजे आया, जिसमें दावा किया गया कि लवली पब्लिक स्कूल के अंदर विस्फोटक रखा गया है।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। मौके पर तुरंत कई फायर टेंडर, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीमें भेजी गईं।सावधानी के तौर पर छात्रों, शिक्षकों और पूरे

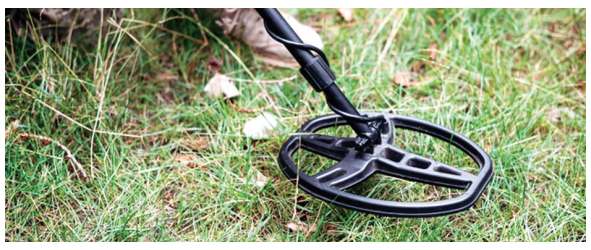

स्टाफ को स्कूल भवन से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। साथ ही स्कूल परिसर को पूरी तरह घेरकर जांच शुरू कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की सूचना नहीं है। गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल डीएलएफ फेज-3 में दोपहर 12.10 बजे बम होने की सूचना मिली। ईमेल से मिली जानकारी। स्कूल को खाली करवाकर पुलिस ने स्कूल जांचा। डॉग स्क्वायड और बम स्क्वाड टीमों ने स्कूल का निरीक्षण किया। कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ अफवाह थी। किसी ने डर फैलाने के लिए मेल भेजी है। मेल का आईपी एड्रेस निकालकर जांच की जा रही है। मेल भेजकर अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दो कारों की टक्कर के बाद लगी आग, पांच की मौके पर ही मौत

एजेंसी

बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार को डीह गांव के पास खड़ी वैगन आर में पीछे से तेज रफ्तार ब्रेजा कार टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन धू-धूकर जल उठे। हादसे में महिला व किशोरी समेत पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए जिनमें दो की हालत बेहद नाजुक है। दोनों वाहनों में नौ लोग सवार थे। सभी घायलों को सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती करवाया गया है।हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डीह गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर खड़ी एक वैगन आर में पीछे से

ब्रेजा ने टक्कर मार दी, जिससे वैगन आर में लग गई और दोनों वाहन जलने लगे। घटनास्थल पर पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौजूद हैं। मामले की जांच की जा रही है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि एक कार गाजियाबाद की जबकि दूसरी दिल्ली की है। माना जा रहा है कि कार में पति-पत्नी और दो बच्चे थे। यह लोग पानी पीने के लिए कार रोक कर निकले थे तभी दूसरी कार आ टकराई।

दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम

ड्रोन-फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत अब राजधानी दिल्ली-NCR को मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट हमले जैसे खतरों से बचाने के लिए अपना खुद का मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के अनुसार नया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम (IADWS) पूरी तरह देश में बने हथियारों से तैयार होगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा DRDO की बनाई QRSAM मिसाइल और VSHORADS होगा। इनके साथ कई तरह के सेंसर, रडार और एक आधुनिक कंट्रोल सिस्टम जोड़ा जाएगा, जिससे हर खतरे पर तुरंत नजर रखी जा सके। ये पूरा सिस्टम भारतीय वायुसेना ऑपरेट करेगी। कअउहर का 23 अगस्त को सफल परीक्षण भी हो चुका है। IADWS एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये दुश्मन के हवाई हमले नाकाम करेगा। इसे सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। यह स्वॉर्म (एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन्स) ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर

IADWS का सफल परीक्षण किया गया था। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए पोस्ट में लिखा था- इस परीक्षण ने हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाई है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देगा। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन, मल्टी कॉप्टर ड्रोन समेत तीन अलग-अलग टारगेट पर अटैक किया। ये तीनों टारगेट अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर थे। IADWS ने इन तीनों को एक साथ निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस तरह से तैयार किया गया है कि पहले रडार यूनिट आने वाले खतरों पर नजर रखती है और उन्हें क्लासिफाई करती है। इसके बाद कमांड सेंटर ज्यादा ऊंचाई से आने वाले तेज खतरों के लिए क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) को निर्देश देता है। कम रेंज वाले और धीमी गति से होने वाले हमले के लिए एडवांस्ड वैरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें (VSHORADS) एक्टिवेट होती हैं। इसके साथ ही साथ ड्रोन और चीप सैचुरेटेड अटैक के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) हमला करते हैं। अमेरिका के महंगे NASAMS-II की जगह स्वदेशी सिस्टम भारत पहले अमेरिका का NASAMS-II सिस्टम खरीदना चाहता था, जो वॉशिंगटन DC और व्हाइट हाउस की सुरक्षा करता है। इसके लिए बातचीत भी चली, लेकिन उसका खर्च बहुत ज्यादा था। इसके बाद सरकार ने पूरी तरह स्वदेशी विकल्प अपनाने का फैसला किया। यह कदम 'मेक इन इंडिया' रक्षा सेक्टर के लिए बड़ी बढ़त माना जा रहा है। DRDO मिसाइल सिस्टम को रडार, डेटा लिंक और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ने की जिम्मेदारी संभालेगा।

शशि थरूर ने वीर सावरकर अवॉर्ड लेने से इनकार किया

बोले: आयोजकों ने बिना पूछे नाम घोषित किया, एनजीओ का दावा: कांग्रेस सांसद ने सहमति दी थी

एजेंसी

नई दिल्ली। वीर सावरकर पुरस्कार को लेकर चल रही चचाओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान थरूर ने कहा कि उन्होंने यह पुरस्कार कल ही (मंगलवार) के दिन सुना और वे पुरस्कार समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में कल ही सुना। मैं वहां नहीं जा रहा हूं। शशि थरूर ने साफ किया कि वह वी.डी. सावरकर के नाम पर दिया जाने वाला कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे और न ही इससे जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने यह भी कहा कि मेरी सहमति के बिना मेरा नाम घोषित करना आयोजकों की ओर से गैरजिम्मेदाराना हरकत थी।थरूर के बयान के बाद पुरस्कार देने वाली हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस) इंडिया के सचिव अजी कृष्णन ने एक टीवी चैनल को बताया कि कांग्रेस सांसद को इस मामले की जानकारी काफी पहले ही दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि एचआरडीएस इंडिया के प्रतिनिधियों और पुरस्कार जूरी के

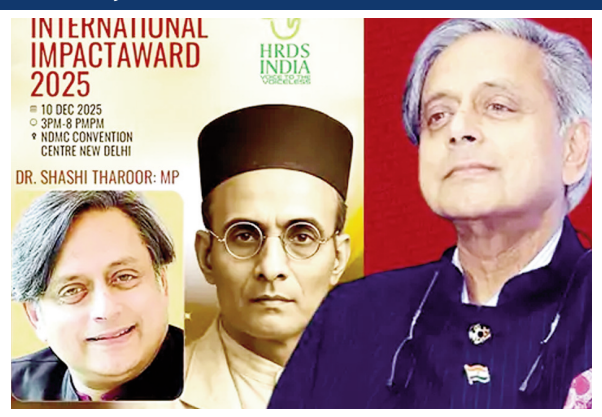

अध्यक्ष ने थरूर को आमंत्रित करने के लिए उनके आवास पर उनसे मुलाकात की थी और सांसद ने पुरस्कार के अन्य प्राप्तकताओं की सूची मांगी थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा, 'हमने उन्हें सूची दे दी थी। उन्होंने अभी तक हमें सूचित नहीं किया है कि वे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। शायद वे डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर एक पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने कहा, 'पुरस्कार की प्रकृति, इसे प्रदान करने वाले संगठन या किसी अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में, आज कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति या पुरस्कार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालने के लिए केरल जाने पर उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बच्चों के कल्याण के लिए यूनिसेफ से बढ़ती उम्मीदें

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

- यूनिसेफ की स्थापना के 79 वर्ष

(यूनिसेफ स्थापना दिवस (11 दिसम्बर) पर विशेष)

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तबाह हुए देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 दिसम्बर 1946 को न्यूयार्क में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। उस समय इसे 'यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड' के नाम से जाना जाता था। विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विस्तारित किया गया। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से 'अंतर्राष्ट्रीय' तथा 'आपातकालीन' (इमरजेंसी) शब्दों को हटा दिया गया। 1953 में यूनिसेफ के संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाने के बाद इसका नाम 'यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड' (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) कर दिया गया लेकिन मूल संक्षिप्त नाम 'यूनिसेफ' को बरकरार रखा गया। यूनिसेफ का गठन करने में पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉथमन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद देने तथा उनकी प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने का दायित्व यूनिसेफ को सौंपा गया है, जो बाल अधिकार समझौते से मार्गदर्शन लेते हुए बाल अधिकारों को चिरंतन नैतिक सिद्धांतों और बच्चों के प्रति व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्थापित करने के लिए सदैव प्रत्यनशील रहता है।

अपनी स्थापना के बाद के इन 79 वर्षों में यूनिसेफ ने दुनियाभर में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विश्वभर में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तथा वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तुरियस अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। नोबेल पुरस्कार दिए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर यूनिसेफ का कार्य और तेज हो गया। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो यूनिसेफ की शिक्षा इकाई के कारण ही वर्ष 2006 तक विश्वभर में करीब 12 मिलियन बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल वापस जा सके। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए यूनिसेफ आपात स्थितियों में कार्रवाई करता है और युद्ध, आपदा, घोर गरीबी, हर प्रकार की हिंसा और शोषण तथा विकलांगता से पीड़ित सर्वाधिक वंचित बच्चों के लिए विशेष संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। यह बच्चों को पहला अधिकार दिलाता है और वंचित बच्चों तथा उनके परिवारों के लिए उपयुक्त नीतियां बनवाने और सेवाएं प्रदान करने की देशों की क्षमता का निर्माण करता है।

1946 में यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय युद्ध में प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से ही की गई थी लेकिन अब यह संस्था दुनियाभर में बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत है। वर्तमान में यूनिसेफ के कार्यकर्ता दुनियाभर के 190 से भी अधिक देशों में बच्चों के कल्याण के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं। भारत में इस संस्था ने वर्ष 1949 में कार्य करना प्रारंभ किया था और अब हमारे यहां यह नई दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में कार्य कर रही है। बाल विकास और पोषाहार, बाल संरक्षण, शिक्षा, बाल पर्यावरण, पोलियो उन्मूलन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, बच्चे और एड्स, सामाजिक नीति, नियोजन, निगरानी एवं मूल्यांकन, हिमायत और भागीदारी, आचरण परिवर्तन संदेश, आपात स्थिति तैयारी और कार्रवाई जैसे क्षेत्रों पर यूनिसेफ का मुख्य फोकस रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग के अलावा यूनिसेफ द्वारा दुनियाभर में मौजूद अनेक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, इंफेक्शंस आदि के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दुनियाभर में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए तीन बिलियन से भी अधिक टीके प्रदान किए जाते हैं। यूनिसेफ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह संस्था दुनियाभर में बच्चों के कल्याण हेतु कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करती। यह संस्था 49 से भी अधिक देशों में एचआईवी/एड्स से बचाव की लड़ाई में निरन्तर कार्यरत है।

यूनिसेफ का 36 सदस्यों का कार्यकारी दल इसके कार्यों की देखरेख करता है, इसकी नीतियां बनाता है तथा यूनिसेफ के वित्तीय एवं प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों अथवा क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालय, मुख्यालय और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालय तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करते हैं। सात क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकतानुसार सभी देशों में स्थित कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्वस्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। इस संस्था का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों तथा निजी दानदाताओं द्वारा किया जाता है। संस्था के संसाधनों का दो-तिहाई योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं और शेष योगदान निजी समूहों तथा व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से किया जाता है। यूनिसेफ के लक्ष्यों की एक लंबी सूची है, जिसमें न्यूनतम-लागत हस्तक्षेप के माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन को बचाने, बच्चों के अवैध व्यापार और शोषण को रोकने तथा मां-बच्चे के बीच एचआईवी/एड्स के संक्रमण को समाप्त करने में सहायता करना शामिल हैं। अनुमान लगाया जाता रहा है कि यूनिसेफ के राजस्व का करीब 92 फीसदी हिस्सा सेवा कार्यक्रमों के लिए वितरित कर दिया जाता है। वर्तमान में यूनिसेफ द्वारा बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा सहित लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी/एड्स, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष इत्यादि के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं।

यूनिसेफ इस बात में विश्वास रखता है कि बच्चों का पोषण और देखभाल करना मानव प्रगति की आधारशिला है और उसका मानना है कि अगर दुनिया में फैली असमानता को मिटाया नहीं गया तो वर्ष 2030 तक लगभग 167 मिलियन बच्चे भीषण गरीबी में जीवन जीने को मजबूर होंगे। दरअसल माना जा रहा है कि 2030 तक पांच वर्ष से कम आयु के करीब 19 मिलियन बच्चों की विभिन्न कारणों से मौत हो जाएगी और करीब 60 मिलियन बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध ने इन चुनौतियों को और बढ़ाया है। ऐसे में बच्चों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत यूनिसेफ से उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं, जिसकी नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर ही अनाथालयों को केवल बच्चों के लिए अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। दरअसल यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता रहा है। उसका कहना है कि जहां तक संभव हो, परिवारों और समुदायों में ही बच्चों के लिए स्थान खोजने अर्थात् उन्हें गोद देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूनिसेफ अनाथ बच्चों को विदेशी माता-पिता को गोद देने के बजाय स्वदेश में ही बच्चों की देखभाल करने पर जोर देता रहा है।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संपादकीय

बच्चों पर संकट

इस सदी के ढाई दशक में बाल मृत्यु दर घटने को दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया था, लेकिन अब इस सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि की आशंका जतायी जा रही है। गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है दुनिया भले ही अमीर हो गई है लेकिन गरीब देशों के बच्चों पर होने वाला खर्च घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धनी देशों द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य खर्च पर 27 फीसदी की कटौती की गई है। जिससे इस वर्ष दो लाख अतिरिक्त बच्चों की मौत की आशंका जतायी जा रही है। दरअसल, ये मौतें उन बीमारियों से हो सकती हैं, जिन्हें अमीर देशों से मिलने वाली मदद से होने वाले टीकाकरण और बुनियादी इलाज से टाला जा सकता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं कि जिस समय दुनिया में संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस समय गरीब देशों के बच्चों पर स्वास्थ्य खर्च का घट जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। आशंका जतायी जा रही है कि यदि स्वास्थ्य सहायता में तीस प्रतिशत की कटौती हो जाती है तो वर्ष 2045 तक 1.6 करोड़ अतिरिक्त बच्चों की मौत हो सकती है। विडंबना देखिए कि इस आसन्न संकट को नजरअंदाज करके विकसित देश अपने रक्षा व आंतरिक खर्च को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि अमीर देशों द्वारा गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य के लिये दिया जाने वाला पैसा उनके बजट के एक फीसदी से भी कम है। गेट्स फाउंडेशन का विश्व के अमीर देशों से आग्रह है कि वे दुर्लभ संसाधनों को उन स्थानों पर लक्षित करें, जहां वे सबसे अधिक जीवन बचा सकते हैं। दरअसल, संकट में वे बच्चे हैं, जो अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस संकट बढ़ने से दशकों से हासिल वैश्विक प्रगति बेकार हो जाएगी। निस्संदेह, दुनिया में कहीं भी पैदा हुए बच्चे को जीवित रहने और फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए। दरअसल, गेट्स फाउंडेशन की गोलकीपर्स रिपोर्ट और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने बताया कि 2024 में, 4.6 मिलियन बच्चों की पांचवें जन्मदिन से पहले मौत हो गई थी। आशंका है कि आर्थिक मदद में कटौती से इस वर्ष इस संख्या में दो लाख की वृद्धि से इसके बढ़कर 4.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की आशंका है। जिसकी मूल वजह स्वास्थ्य के लिये वैश्विक मदद में आई बड़ी गिरावट है। इस वर्ष सहायता निधि में भारी कटौती के अलावा गरीब देशों के बढ़ते कर्ज, कमजोर स्वास्थ्य सिस्टम के चलते मलेरिया, एचआईवी और पोलियो जैसी बीमारियों के विरुद्ध हासिल उपलब्धियों को खोने का जोखिम बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्ट बताती है कैसे प्रमाणित समाधानों और अगली पीढ़ी के नवाचारों में लक्षित निवेश से सीमित बजट में लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। निस्संदेह, गरीब मुल्कों के ये बच्चे सुरक्षित जीवन पाने के हकदार हैं। गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स कहते हैं विश्व में गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये वित्तीय संसाधन बढ़ाने व वर्तमान सिस्टम में सुधार हेतु दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हमें कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पीढ़ी के दामन पर दाग लगेगा कि मानव इतिहास में सबसे उन्नत विज्ञान और नवाचार की पहुंच के बावजूद हम लाखों बच्चों का जीवन बचाने के लिये धन नहीं जुटा पाए। हम सही प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं तय करके तथा उच्च प्रभाव वाले समाधानों में निवेश करके बाल मृत्यु दर वृद्धि को रोक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम वर्ष 2045 तक कई मिलियन बच्चों को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं।

पहाड़ केवल ज़मीन नहीं, प्रकृति के शृंगार हैं

(लेखक- दिलीप कुमार पाठक)

(11 दिसम्बर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस)

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनओ ने 2003 में पर्वतों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में घोषणा की। पर्वत न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं बल्कि यह वनस्पति, जलीय स्रोत और जैव विविधता के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्वतों की सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व को समझाना है, पर्वतों की स्थिति में भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं। देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत भाग पर्वतों से आच्छादित है।

पर्वतों की सुरक्षा के लिए सतत विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और भीषण दोहन के कारण आज पहाड़ों पर गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं, अनियंत्रित और अत्यधिक पर्यटन ने प्रदूषण, विशेष रूप से गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे की समस्या को गंभीर बना दिया है। पर्वतीय कस्बों में अपशिष्ट निपटान की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है। बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अति-दोहन किया जा रहा है। अरावली जैसी पर्वतमालाओं में अनियंत्रित खनन ने पर्यावरण को गंभीर रूप से घायल किया है, जिससे मरुस्थलीकरण और जल संकट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। पर्वतीय समुदायों को अक्सर गरीबी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पर्वत न केवल पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि तालाबों में बसे लाखों लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हैं दुनिया की प्रमुख नदियाँ और जल चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं। इस दिन पहाड़ों के विकास और उनसे मिलने वाले अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह लोगों को पर्यावरण में पर्वतों की भूमिका और उनके जीवन पर प्रभाव के बारे में शिक्षा देता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का इतिहास 1992 से शुरू हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के अध्याय 13 में संवेदनशील प्रशिक्षण तंत्र का प्रबंधन- सतत विकास के तहत विशिष्टता को शामिल किया गया था। यह पर्वत विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। पहाड़ों के महत्व की ओर बढ़ते ध्यान को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 2003 से हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का निर्णय लिया। इसलिए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2003 को मनाया गया था।

पर्वतों में प्रकृति के अनमोल रत्न शामिल हैं जिनका हमें संरक्षण करना चाहिए। ये हैं दुनिया की 15त्न आबादी के घर और आसपास के आदिवासियों के समूह में शामिल हुए हैं। पहाड़ के किसानों को जीवन के लिए ताज़ा पानी उपलब्ध कराते हैं, कृषि को बनाए रखते हैं और स्वच्छ ऊर्जा और औषधियों की आपूर्ति में मदद करते हैं। दुर्भाग्य से, जलवायु परिवर्तन, भारी दोहन और प्रदूषण के कारण पर्वत खतरे में हैं, जिससे न केवल पर्यावरण बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। जैसे-वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, पर्वतीय तापमान बढ़ रहा है, जिससे नीचे के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो दुनिया के सबसे गरीब समुदायों में से हैं, जीवित रहने के लिए और भी बड़े-बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। ठेकों के कारण, कृषि, सुपरमार्केट या दुकानदारों के लिए किसानों को साफ करने से मिट्टी का कटाव और आवासों का नुकसान हो सकता है। कटाव और प्रदूषण न केवल जल प्रवाह की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मिट्टी की वास्तुकला को भी कम करते हैं। दरअसल, पूर्वोत्तर देशों में 311 मिलियन ग्रामीण पर्वतीय लोग क्षेत्र में रहते हैं, जहां भूमि का स्थिरीकरण हो रहा है, और इनमें से 178 मिलियन लोग खाद्य सुरक्षा के खतरे का सामना कर रहे हैं। यह समस्या हम सभी को प्रभावित करती है। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना चाहिए और इन प्राकृतिक खजानों की देखभाल करनी चाहिए। आज का दिन पर्वतों के जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह पर्वतीय विकास से जुड़े अवसरों और परिचय को दर्शाता है और पहाड़ी इलाकों और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है।

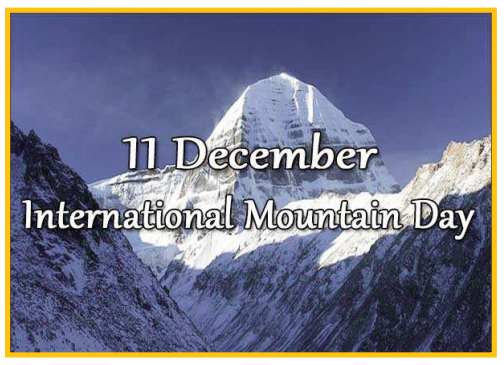

पर्वत हमारे पर्यावरण, जीवन और संस्कृति का हिस्सा हैं। संबंधित तथ्यों का पता लगाना केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करना भी आवश्यक है। पर्वत प्रकृति की अनमोल देन हैं, इन्हें संरक्षित रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

(लेखक पत्रकार हैं)

मन की तेज गति

नौका नदी के उस पार जा रही थी। अनेक व्यक्ति उस पर सवार थे। भार अधिक हो गया। नौका डगमगाने लगी। नाविक ने कहा - नौका डूब जाएगी। यदि सबको बचना है तो स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपना सारा सामान नदी में बहा दो, अन्यथा सामान के साथ-साथ प्राण भी जाएंगे। सबने अपने जीवन की सुरक्षा को महत्व देते हुए सामान नदी में डाल दिया। एक बनिये के पास तीन खाली डिब्बे और एक रूपयों से भरा डिब्बा था। उसने खाली डिब्बे पानी में डाल दिए। नाविक ने कहा - इस वजनी डिब्बे को डाल दो। बनिये ने रूपयों को ऐसे व्यर्थ बहाना उचित नहीं समझा। वह डिब्बे को साथ ले नदी में कूद पड़ा। नौका हल्की हो गई। पर वह बनिया उस डिब्बे के भार से दबकर डूब गया। यदि वह खाली डिब्बे के साथ कूदता तो संभव है बच जाता, पर भरे हुए डिब्बे ने उसे डुबो दिया।

कहने का अर्थ यह है कि लोगों का भरे हुए पर अधिक विश्वास है, खाली पर नहीं। काम में लगे रहते हैं तो समझते हैं भरे हुए हैं, समय का उपयोग हो रहा है। जब खाली होते हैं तब समझते हैं, आज तो समय व्यर्थ खो रहे हैं। लोग खाली रहना नहीं जानते और खाली रहने के समय का उपयोग करना भी नहीं जानते। आदमी खाली कहां रह पाता है? जब उसके पास कोई काम नहीं होता, तब भी वह खाली नहीं है। उसके मन का चक्का इतनी तीव्र गति से घूमता है कि दुनिया की सारी स्मृतियां उस समय उभर आती हैं। मस्तिष्क विचारों से, संकल्प-विकल्पों से भर जाता है। कहां है खाली वह आदमी? उसका दिमाग भरा ही रहता है।

विचार मंथन

चुनाव सुधार और 'वोट चोरी' पर संसद में बहस

(लेखक - सनत जैन)

लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाये रखने का एक अवसर

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हाल ही में हुई बहस में 'वोट चोरी' और व्यापक चुनाव सुधारों का मुद्दा जिस गंभीरता से सभी पक्षों के सांसदों द्वारा उठाया गया, वह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के लिए इसे एक निर्णायक अवसर माना जा सकता है। मतदान प्रक्रिया पर बढ़ते सवाल, तकनीकी, पारदर्शिता को लेकर विपक्ष की आशंकाएँ निराधार नहीं है। चुनाव में अर्थतंत्र की भूमिका का असर, चुनाव के यह मुद्दे लंबे समय से देश की राजनीति और चुनाव में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। इस बार संसद में जिस तीखेपन और स्पष्टता के साथ इन सभी प्रश्नों को सांसदों ने रखा है, उससे सरकार और चुनाव आयोग दोनों के ऊपर चुनाव में सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाने का दबाव बनाने का काम किया है। चुनाव आयोग और सरकार की जवाबदेही तय करने की दिशा में संसद आगे बढ़ी है। बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा, कि चर्चा में वोट चोरी मामले को लेकर सभी गंभीर दिखे। लगभग सभी दलों ने 'वोट चोरी' चुनाव में सरकार के 'अनुचित प्रभाव' तथा चुनाव आयोग का सत्ताधारी दल के प्रति समर्पण जैसे आरोपों की पृष्ठभूमि में चुनाव प्रक्रिया के भरोसे को लेकर विपक्ष की चिंता देखने लायक थी। विपक्ष ने हर बात को बड़ी सूक्ष्मता के साथ संसद में रखा है। इस बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की तलखी देखने को मिली है। सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने जिस तरह की एकजुटता मजबूती के साथ दिखाई है, उससे चुनाव आयोग और सरकार की परेशानी निश्चित रूप से बढ़ी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं कुछ सदस्यों ने ईवीएम से जुड़ी पारदर्शिता को बढ़ाने, वीवीपैट की संख्या में वृद्धि करने, 100 फ़ीसदी मतपत्रों की गिनती करने, और स्वतंत्र ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया है। संसद में विपक्ष के सदस्यों ने डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे का उल्लेख करते हुए मतदान प्रणालियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुधार करने एवं जवाबदेही तय करने की बात कही है। सदन में स्वीकार किया गया है, चुनावी सुधार केवल तकनीकी बदलावों तक सीमित नहीं हो सकते। काले धन और चुनावी खर्च की सीमा के उल्लंघन ने चुनाव को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ा है। राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे में पारदर्शिता, चुनावी बॉन्ड, सरकारी खजाने से चुनाव के दौरान मतदाताओं के खाते में राशि ट्रांसफर करने एवं पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने, विवादित तंत्रों एवं पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का उल्लेख संसद में करते हुए इनमें सुधार की मांग की गई है। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड पर कड़े नियम बनाने के मांग और बहस ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। कई सदस्यों ने मांग दोहराई, दोषी राजनीतिक व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया को विकसित किया जाना जरूरी है।

वोट चोरी' से जुड़े आरोप लोकतंत्र में जनता के विश्वास को चोट पहुँचाते हैं। सदस्यों की मांग थी, संसद में उठे मुद्दों को केवल चर्चा और बहस की औपचारिकता नही माना जाए। संसद में चुनाव सुधार और वोट चोरी को लेकर जो चर्चा हुई है, उस पर तुरंत गंभीरता के साथ आधार बनाकर चुनावी प्रणाली को विश्वसनीय बनाने के लिए और चुनाव में लोगों का भरोसा बना रहे, उसके लिए आवश्यक परिवर्तन करने की जरूरत है। सरकार और चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेकर चुनाव सुधार की दिशा में ठोस, समयबद्ध, पारदर्शी सुधार लागू किए जाने की दिशा में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लोकतंत्र की शक्ति तभी सुरक्षित रह सकती है जब चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, विश्वासप्रद और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। इस पर सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को विश्वास हो। संसद में हुई बहस ने देश को एक बड़ा संदेश दिया है। भारत सरकार और चुनाव आयोग के पास अब चुनाव सुधारों को टालने का विकल्प नहीं बचा है। जिस तरह के हालात पूरे देशभर में बने हैं। एसआईआर के बाद जिस तरह से मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। मतदाता सूची समय पर राजनीतिक दलों और आम जनता के समक्ष नहीं रखी जा रही है। मतदान के बाद जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाता है। वीवीपीएटी की मशीनों के पर्चियों की गणना नहीं की जाती है। उसके कारण राजनीतिक दलों और आम जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से खत्म होता जा रहा है। मतदाताओं का भरोसा पुनः मजबूत करने के लिए संसद में विपक्ष ने जिस तरह के सुझाव दिए हैं उन पर तुरंत सुधार किए जाने की जरूरत है। चुनाव आयोग की नियुक्ति और एसआईआर को चुनाव आयोग सरकार और न्यायपालिका की भूमिका को लेकर भी संसद में बहुत कुछ कहा गया है। जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, न्यायपालिका से चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई को लंबे समय तक टाला जा रहा है। उसके कारण चुनाव और चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर लगातार शक-सुबहा बढ़ता ही चला जा रहा है। संसद में हुये इस विमर्श ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग तथा न्यायपालिका को एक मौका दिया है। समय रहते इस पर सार्थक पहल हो जाती है तो लोगों का इस पर भरोसा बना रहेगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रेपो रेट में कटौती के बाद एचडीएफसी, पीएनबी, बीओबी ने होम लोन की दरें घटाई

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर को अपनी रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25फीसदी कर दी है। इसके बाद एचडीएफसी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बड़े बैंकों ने होम लोन और अन्य रिटेल लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। यह कदम मौजूदा और नए कर्जदारों दोनों के लिए राहत का संकेत है। ज्यादातर बैंक अपने लोन की दरें बाहरी बेंचमार्क या आंतरिक बेंचमार्क के आधार पर तय करते हैं। जब आरबीआई की दर घटती है, तो बैंक अपने बेंचमार्क दरों को भी कम कर देते हैं। फ्लोटिंग रेट होम लोन वाले लोग अपने अगले रीसेट डेट को ध्यान से देखें और यह जानें कि उनका लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है। नए लोन लेने वाले कर्जदार कई बैंकों के ऑफर और फीस की तुलना जरूर करें, क्योंकि स्प्रेड और फीस से लंबी अवधि में लोन की कुल लागत प्रभावित हो सकती है।

अमेरिकी बैन के बाद भी रूसी कच्चा तेल भारत पहुंच रहा, आपूर्ति करने वाले नए विक्रेता उभरे

नई दिल्ली। भारत के निजी क्षेत्र और सरकारी रिफाइनरियों को अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आपूर्ति की अंतिम तिथि 21 नवंबर के बाद भी रूस के आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा तेल हासिल करना जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट में रिफाइनिंग के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति करने वाले नए मध्यस्थ उभर आए हैं। मैरीटाइम इंटेलिजेंस एजेंसियों केप्लर और वोर्टेक्सा के डेटा से पता चला कि अभी भी कुछ कार्गो ने रूस के सबसे बड़े तेल उत्पादक प्रतिबंध वाले रोसनेफ्ट से आपूर्ति हासिल की है। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल के नए विक्रेता जैसे अल्गाफ मैरीन, रेडवुड ग्लोबल सप्लाई, रसएक्सपोर्ट, रूसवियतपेट्रो, नेफ्टिसा, डक्कॉर, मोरएक्सपोर्ट, ग्रीवाले हब एफजेडई और ईस्ट इम्प्लेक्स स्ट्रीम एफजेडई जैसी कंपनियां शामिल हैं। केप्लर के अधिकारी ने कहा कि डेटा लेन-देन में इस्तेमाल किए गए लदान के बिलों में दी गई खरीदारों और विक्रेताओं की जानकारी पर आधारित है। एनर्जी इंटेलिजेंस ने बताया कि प्राइमग्रोथ, ओरिक्स, ऑगस्टा, अमूर इन्वेस्टमेंट्स और नेक्सस समेत यूएई में रूसी कच्चे तेल के अन्य विक्रेता है। इसकी पुष्टि भारतीय रिफाइनरियों ने भी की है। रिफाइनिंग क्षेत्र के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि नए विक्रेताओं का उदय भारत और रूस दोनों देशों के उत्पादकों और रिफाइनरियों के लिए 50 अरब डॉलर के महत्व को दर्शाता है। यहां तक कि रूसी तेल पर दी जाने वाली छूट 2023 के बाद से सबसे ज्यादा हो गई है और 2025 की शुरुआत से तीन गुना हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिमी एशिया और अमेरिका से वैकल्पिक आपूर्ति बहुत ज्यादा होने के बावजूद बहुत महंगी है। फिनिश ऊर्जा थिंक टैंक सीआरईए के मुताबिक अमेरिका ने मूलरूप से नवीनतम प्रतिबंधों में भारतीय रिफाइनरियों को रूस की बिक्री को निशाना बनाया है, वहीं यूरोपीय संघ और चीन छूट प्राप्त रूसी कमोडिटी आपूर्ति के सबसे बड़े लाभार्थी हैं और उन्होंने रूसी युद्ध प्रयासों में अरबों डॉलर का योगदान दिया है। सीआरईए के मुताबिक फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत से लेकर 6 दिसंबर, 2025 तक चीन ने तेल, गैस और कोयले के आयात के लिए रूस को 288 अरब यूरो यानी 334 अरब डॉलर का भुगतान किया। इस क्रम में यूरोपीय संघ ने 217 अरब यूरो का भुगतान किया। भारत ने 161 अरब यूरो और तुर्की ने 117 अरब यूरो का भुगतान किया। केप्लर के दिसंबर के शुरुआती आंकड़े से पता चलता है कि रोसनेफ्ट के 21 नवंबर के बाद भेजे गए 25 जहाज में से 16 जहाज भारत पहुंचे। इसमें से छह जहाज जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिए गए और पांच पार्सल नायरा के वाडिनार संयंत्र को भेजे गए। केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक शेष जहाज सरकारी कंपनियों जैसे भारत पेट्रोलियम आदि को मिले।

आरबीआई गवर्नर का सरकारी और निजी बैंकों को सुझाव, बैंकिंग सिस्टम में मध्यस्थता लागत को कम करें

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सरकारी और कुछ चुनिंदा निजी बैंकों के प्रबंधक निदेशकों और सीईओ को कहा कि अपने बैंकिंग सिस्टम में मध्यस्थता लागत को कम करें और दक्षता को बढ़ावा दें। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा का यह बयान तब आया है, जब हाल ही मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) की ओर से ब्याज दर को 25 आधार अंक या 0.25 प्रतिशत कम किया है, जिससे रेपो रेट कम होकर 5.25 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 5.50 प्रतिशत था। इस फरवरी 2025 से आरबीआई रेपो रेट में 125 आधार अंक की कटौती कर चुका है।

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा है कि 125 आधार अंकों की ब्याज दर में कमी और प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से मध्यस्थता लागत कम होगी और दक्षता बढ़ेगी। आरबीआई के बयान में कहा गया कि ये बातचीत जनवरी 2025 में हुई इस तरह की बैठकों के बाद विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ रिजर्व बैंक की चल रही सहभागिता का हिस्सा हैं।

साथ ही, मल्होत्रा ने बैंकों से शिकायतों को कम करने और आंतरिक प्रणालियों को बेहतर करने का आग्रह किया। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिमों पर फोकस करने और अधिक मजबूत, इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा उपायों को बैंकों को अपनाने का सुझाव दिया। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों द्वारा

रीकेवाईसी और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की सराहना कर सक्रिय संपर्क और सतत जागरूकता अभियानों को बढ़ाया है। बयान में कहा गया है कि मुलाकात में प्रतिभागियों ने नीति, पर्यवेक्षण और परिचालन संबंधी विभिन्न मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण साझा किए।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया बुधवार को सात पैसे की गिरावट के साथ ही 89.92 पर बंद हुआ। पिछले सत्र में रुपया 89.85 पर बंद हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि वैश्विक बाजारों में डॉलर की मांग बढ़ने का असर घरेलू मुद्रा पर जारी है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर की मजबूत खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता के कारण निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव स्थानीय मुद्रा पर दिखाई दिया, जो हल्की गिरावट के साथ व्यापार की शुरुआत कर रहा है। कारोबारियों का कहना है कि विदेशी निवेश प्रवाह और वैश्विक आर्थिक संकेतकों में उतार-चढ़ाव भी रुपये की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 99.04 पर रहा, जिससे संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डॉलर में हल्की नरमी दर्ज हुई है।

भारत में करीब 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड-एआई को मिलेगा बढ़ावा

-यह घोषणा कंपनी के चेयरमैन ने पीएम मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद की

नई दिल्ली।

सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को घोषणा की कि वह 2026 और 2029 के बीच भारत में करीब 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह निवेश भारत के क्लाउड और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और परिचालन को बढ़ावा देने के लिए होगा। कंपनी ने यह साफ किया कि यह नया निवेश, इस साल जनवरी में भारत के लिए घोषित तीन अरब डॉलर के निवेश के अतिरिक्त होगा। माइक्रोसॉफ्ट की घोषणा उसके चेयरमैन और मुख्य कार्याधिकारी सत्य नडेला ने मंगलवार शाम पीएम मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद की। इस बैठक में भारत के एआई रोडमैप और इसके विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि जब एआई की बात आती है तब दुनिया 'भारत को लेकर आशावादी है'। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि भारत वह जगह है जहां माइक्रोसॉफ्ट, एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इसका फायदा उठाकर नवाचार करेंगे और एआई की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इस नए निवेश का इस्तेमाल कंपनी के क्लाउड और एआई से जुड़े बुनियादी ढांचे, कौशल विकास पहल और पूरे भारत में चल रहे परिचालन का दायरा बढ़ाने में किया जाएगा।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 275, निफ्टी 81अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को भी गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बिकवाली हावी रहने से आई है। यह लगातार तीसरा दिन रहा जब घरेलू बाजार में गिरावट रही। आज दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 275.01 अंकों करीब 0.32 फीसदी टूटकर 84,391.27 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 81.65 अंक फिसलकर 25,758 पर बंद हुआ। आज सुबह बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही पर समय के साथ ही इसमें गिरावट आने लगी। जानकारों के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के परिणामों से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से भी बाजार गिरा है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से भी बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.90 फीसदी तक गिरा। वहीं स्मॉलकैप शेयरों में भी 0.42 फीसदी तक की गिरावट रही। आज सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बिकवाली रही। वहीं बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी।

सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, सनफार्मा, आईटीसी, एनटीपीसी और एचसीएल टेक के शेयर लाभ में रही। वहीं भारती एयरटेल, इन्फोसिस के शेयरों में बिकवाली रही। जापान में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी रहा,। अब सबकी नजर आने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है, जहां माना जा रहा है कि 0.25 फीसदी की ब्याज दर में कटौती की जाएगी। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, रुपए की कमजोरी और अमेरिका वभारत व्यापार को लेकर संशय ये भी बाजार धारणा कमजोर हुई है ।

इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स 84,607 अंक पर सपाट खुला। सुबह ये 136.27 अंक या 0.16 फीसदी की बढ़त के साथ 84,802.55 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह का निफ्टी 25,864 अंक पर सपाट खुला। सुबह यह 20.80 अंक बढ़कर 25,860.45 पर कारोबार कर रहा था।

दूसरी ओर अमेरिकी शेयर बाजार स्थिर रहे। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.1 फीसदी गिरा और अक्टूबर में बने अपने ऑल टाइम हाई के करीब बना रहा। वहीं डॉव जोन्स औसत 179 अंक करीब 0.4 फीसदी नीचे आया। वहीं नैस्डैक कंपोज़िट 0.1 फीसदी बढ़ा। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई ऊंची शुरुआत करने के बाद 0.5 फीसदी फिसला। दक्षिण कोरिया का बाजार 0.4 फीसदी नीचे आया। जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत शेयरों के ब्रोडर इंडेक्स में 0.1 फीसदी की हल्की गिरावट रही। वहीं गत दिवस बाजार गिरावट पर बंद हुआ था।

अपाचे आरटीएक्स 300 का नया सेलिब्रेशन एडिशन पेश

नई दिल्ली ।

गोवा में आयोजित मोटासाउल 2025 इवेंट में टीवीएस ने अपनी एडवेंचर-टूरर बाइक अपाचे आरटीएक्स 300 का नया सेलिब्रेशन एडिशन पेश किया है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण ब्लैक व गोल्ड रंग संयोजन है, जो इसे बाकी मॉडलों से अलग बनाता है। नया एडिशन पूरी तरह से स्टाइलिंग अपडेट पर आधारित है और इसमें इंजन, फ्रेम, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप में कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया गया है। यानी परफॉर्मेंस और राइडिंग अनुभव स्टैंडर्ड अपाचे आरटीएक्स 300 जैसा ही रहेगा। बाइक में ब्लैक बॉडी पैनल पर शैंपेन गोल्ड ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो इसकी डिजाइन लाइंस को और उभारते हैं। रेड हाईलाइट्स के इस्तेमाल से इसमें स्पोर्टी और एग्रेसिव टच भी मिलता है। वहीं डुअल-टोन एलॉय व्हील्स (ब्लैक और गोल्ड) इसका मुख्य आकर्षण बनते हैं। टीवीएस ने सेलिब्रेशन एडिशन में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और राइडर एड्स भी वही रखे हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल में मौजूद हैं और इस बार कोई नया फीचर पैकेज शामिल नहीं किया गया है। कंपनी ने फिलहाल कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह सामान्य मॉडल की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि इसे लिमिटेड एडिशन के रूप में बाजार में उतारा जाएगा।

मीशो के शेयर की जोरदार एंट्री, 161.20 के भाव पर हुए लिस्ट

-निवेशकों को हर लॉट पर 6750 रुपए का हुआ फायदा

नई दिल्ली।

ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के शेयर बुधवार को जोरदार एंट्री के साथ लिस्ट हुए। आईपीओ अप्लाई करने के लिए 3 दिसंबर को खुला था और 5 दिसंबर को बंद हो गया था। मीशो के शेयर बीएसई पर 161.20 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए। यह इश्यू प्राइस बैंड के अपर एंड 111 रुपए से 50 रुपए या 45 फीसदी ज्यादा है। वहीं एनएसई पर कंपनी के शेयर 162.50 रुपए पर लिस्ट हुए, जो इश्यू प्राइस की तुलना में 51.50 रुपए या 47 फीसदी ज्यादा है। मीशो की लिस्टिंग ग्रे मार्केट के अनुमान से भी ज्यादा रही। ग्रे मार्केट में मीशो आईपीओ का जीएमपी बुधवार को 36 रुपए पर चल रहा था। इस प्रीमियम पर मीशो आईपीओ का अनुमानित लिस्टिंग प्राइस करीब 147 रुपए प्रति शेयर माना जा रहा था, जबकि शेयर 161 रुपए पर लिस्ट हुए। आईपीओ के हर लॉट में 135 शेयर थे। इस तरह निवेशकों को हर लॉट पर 6750 रुपए का फायदा हुआ।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मीशो आईपीओ को लेकर बाजार में जोरदार उत्साह देखने को मिला। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक इश्यू को 21,96,29,80,575 शेयरों के लिए बोलियां लगी हैं, जबकि पेशकश 26,86,18,197 शेयर रखे गए हैं। कुल मिलाकर आईपीओ को 2.29 गुना अप्लाई किया जा चुका है। रिटेल निवेशकों की केटेगरी को सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। इसे अब तक 81.76 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने सबसे ज्यादा 123.34 गुना अप्लाई किया। जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल खरीदारों ने 39.85 गुना और रिटेल निवेशकों ने 19.89 गुना बुक किया।

स्पेसएक्स अब शेयर मार्केट में उतरेगी, 30 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा जुटाने की तैयारी

-कंपनी पूरे बिजनेस को करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू पर ले जाना चाहती है

वाशिंगटन,(ईएमएस)। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अब शेयर मार्केट में उतरेगी। कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 30 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा जुटा सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास की सबसे बड़ा लिस्टिंग साबित होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने पूरे बिजनेस को करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 1 लाख 50 हजार अरब डॉलर की वैल्यू पर ले जाना चाहती है। ये वैल्यू सऊदी अरामको के 2019 के रिकॉर्ड के बराबर होगी, जब अरामको ने 29 अरब डॉलर जुटाए थे। अगर ऐसा हुआ तो स्पेसएक्स दुनिया की सबसे महंगी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। स्पेसएक्स एग्जीक्यूटिव 2026 के बीच या आखिर तक कंपनी को शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट की स्थिति देखकर तारीख बदल भी सकती है, और ये आईपीओ 2027 तक भी आ सकता है।

स्पेसएक्स के आईपीओ की खबर के बाद मंगलवार को दूसरे स्पेस कंपनियों के शेयरों में तगड़ा उछाल आया। एकोस्टार कंपनी, जो स्पेसएक्स को स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेच रही है, उसके शेयर न्यूयॉर्क में 12फीसदी तक चढ़ गए और नया रिकॉर्ड बना लिया। रॉकेट लैब कंपनी के शेयर भी 4.3फीसदी तक बढ़ गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एलन मस्क और कंपनी के बोर्ड ने हाल के दिनों में लिस्टिंग और फंड जुटाने के प्लान को तेज कर दिया है, यहां तक कि जरूरी पोस्ट के लिए हायरिंग भी शुरू हो गई और पैसे कहां लगाए जाएंगे इसकी प्लानिंग भी हो रही है। ये सब तब हुआ जब स्पेसएक्स अपनी लेटेस्ट इनसाइडर शेयर सेल को फाइनल कर रही थी।

इस आईपीओ को इतनी जल्दी लाने की एक बड़ी वजह है कि कंपनी का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट बिजनेस जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही मोबाइल पर डायरेक्ट इंटरनेट देने का नया प्लान भी है।

कैनरा बैंक की 15 को बैठक, शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड देने पर लेगा फैसला

-शेयर की कीमत बढ़ने से निवेशक हैं खुश, डिविडेंड मिलने की है उम्मीद

नई दिल्ली।

कैनरा बैंक से जुड़ी कंपनी केन फिन होम्स ने कहा है कि उसका बोर्ड 15 दिसंबर को बैठक करेगा। इस बैठक में कंपनी तय करेगी कि साल 2025-26 के लिए शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड दिया जाए या नहीं। कंपनी के मुताबिक यह फैसला शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और अगर बोर्ड मंजूरी देता है, तो यह डिविडेंड दे दिया जाएगा।

कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए 19 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस दिन तक जिन शेयरधारकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वह डिविडेंड के पात्र होंगे। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने साफ कहा कि बोर्ड द्वारा डिविडेंड की घोषणा किए जाने पर इसी रिकॉर्ड डेट के आधार पर शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा।

इंसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के कारण केन फिन होम्स ने अपने कर्मचारियों, कंपनी से जुड़े लोगों, प्रमोटर्स और उनके करीबी रिश्तेदारों को अभी शेयर खरीदने या बेचने से रोक दिया है। कंपनी ने 17 दिसंबर तक ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है। यह इसलिए किया ताकि कोई भी व्यक्ति कंपनी की अंदरूनी गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर सके और सभी नियमों का ठीक से पालन हो सके। मंगलवार को बाजार में केन फिन होम्स का शेयर 908.40 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से 0.45फीसदी कम है। शेयर की कीमत बढ़ने का मतलब निवेशक खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है और उसका कामकाज भी अच्छा है। इसी वजह से शेयर में तेजी देखी गई।

बता दें पिछले एक महीने में इस शेयर में 3.06फीसदी की बढ़त हुई, जबकि सेनसेक्स सिर्फ 2.44फीसदी बढ़ा। पिछले छह महीनों में कंपनी का रिटर्न 12.31फीसदी रहा, जो सेनसेक्स के 3.72फीसदी से काफी ज्यादा है। एक साल में भी यह शेयर 12.91फीसदी चढ़ा, जबकि सेनसेक्स केवल 4.33फीसदी ऊपर गया। लंबे समय में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले पांच साल में इसका शेयर 89फीसदी बढ़ा, जो सेनसेक्स की 86.91फीसदी बढ़त से बेहतर है।

भारत में करीब 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड-एआई को मिलेगा बढ़ावा

-यह घोषणा कंपनी के चेयरमैन ने पीएम मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद की

नई दिल्ली।

सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को घोषणा की कि वह 2026 और 2029 के बीच भारत में करीब 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह निवेश भारत के क्लाउड और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और परिचालन को बढ़ावा देने के लिए होगा। कंपनी ने यह साफ किया कि यह नया निवेश, इस साल जनवरी में भारत के लिए घोषित तीन अरब डॉलर के निवेश के अतिरिक्त होगा। माइक्रोसॉफ्ट की घोषणा उसके चेयरमैन और मुख्य कार्याधिकारी सत्य नडेला ने मंगलवार शाम पीएम मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद की। इस बैठक में भारत के एआई रोडमैप और इसके विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने कहा कि जब एआई की बात आती है तब दुनिया 'भारत को लेकर आशावादी है'। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि भारत वह जगह है जहां माइक्रोसॉफ्ट, एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इसका फायदा उठाकर नवाचार करेंगे और एआई की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की।

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इस नए निवेश का इस्तेमाल कंपनी के क्लाउड और एआई से जुड़े बुनियादी ढांचे, कौशल विकास पहल और पूरे भारत में चल रहे परिचालन का दायरा बढ़ाने में किया जाएगा। कंपनी ने अपने ब्लॉग में कहा कि यह निवेश बड़ा बुनियादी ढांचा तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा जो देश की सरकार के लिए बना हो, सुरक्षित हो और सरकार उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि इस प्रयास का मुख्य केंद्र, हैदराबाद में बनने वाला इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड क्षेत्र होगा, जो 2026 के मध्य तक शुरू होने के लिए तैयार है।

यह भारत में उनका सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा क्षेत्र होगा जिसमें तीन उपलब्धता वाले क्षेत्र होंगे और इसका आकार ईडन गार्डन स्टेडियम का दोगुना होगा।

नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ 871 करोड़ रुपए सब्सक्राइब खुला, ब्रोकरेज ने दी सलाह

नई दिल्ली।

नेफ्रोप्लस ब्रांड के तहत डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड करने वाली नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज का 871.05 करोड़ रुपए का शुरुआती आईपीओ 10 दिसंबर यानी बुधवार को सब्सक्राइब करने खुला।

निवेशक 12 दिसंबर तक इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्च से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 460 रुपए प्रति शेयर की दर से 260 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 438 से 460 रुपए प्रति शेयर रखा है। एक लॉट में 32 शेयर है।

रिपोर्ट के मुताबिक नेफ्रोकेयर ने अपने इश्यू के जरिए 353.4 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी।

जबकि प्रमोटर और मौजूदा निवेशक ऑफर-फॉर-सेल के जरिये 1.12 करोड़ शेयर बेचेंगे। इन्वेस्टकॉर्प, हेल्थकेयर पैरेंट, एडोरस इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और 360 वन ओएफएस में भाग लेने वालों में शामिल हैं। प्रमुख एंकर निवेशकों में एसबीआई हेल्थकेयर ऑपर्च्युनिटीज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, फिडेलिटी फंड्स, डीएसपी हेल्थकेयर फंड, द प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स, पोलर कैपिटल फंड्स, मनुलाइफ ग्लोबल फंड, बड़ौदा बीएनपी पारिबा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं। नेफ्रोकेयर नए शेयरों के जरिये 353.4 करोड़ रुपए जुटाएगी, जबकि प्रोमोटर और मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए 1.12 करोड़ शेयर तक बेचेंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईसीसी एकदिवसीय रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे विराट, रोहित शीर्ष पर बरकरार

दुबई (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ताजा एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष दो स्थान पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा हो गया है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा जहां नंबर एक स्थान पर बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भारत के ही अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली आ गये हैं। हाल में इन दोनो ने अच्छा प्रदर्शन किया था जिसका लाभ इन्हें मिला है। जिससे रोहित अपनी जगह पर बने हुए हैं जबकि विराट ऊपर आये हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के दौरान ही अपने शानदार प्रदर्शन से आईसीसी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। वह नंबर एक पर बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों में 57, 14, और 75 की पारी से रोहित का नंबर एक स्थान बना रहा। वहीं विराट ने ताजा रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। विराट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज में 135, 102, और 65 रन बनाये। इन तीन पारियों की सहायता से रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गये हैं।

भारतीय टीम के एकदिवसीय प्रारुप के कप्तान शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम छठे, आयरलैंड के हैरी टैक्टर सातवें, वेस्टइंडीज के शाई होप आठवें, श्रीलंका के चरिथ असलांका नौवें और भारत के श्रेयस अय्यर दसवें स्थान पर हैं। फिट नहीं होने के कारण टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वहीं केएल राहुल ने भी दक्षिण अफ्रीका सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की थी और इससे उन्हें दो स्थान का लाभ हुआ है। वह 12वें स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी के कारण दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 3 स्थान ऊपर आकर 13वें नंबर पर आ गये हैं।

द हंड्रेड में नजर आएंगे दिनेश कार्तिक, लंदन स्पिरिट ने दी बड़ी जिम्मेदारी

लंदन (एजेंसी)। भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, जो मौजूदा IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मेंटर भी हैं, को द हंड्रेड फ्रेंचाइजी लंदन स्पिरिट का मेंटर और बैटिंग कोच बनाया गया है। द हंड्रेड के लिए किसी फ्रेंचाइजी में अपनी पहली भूमिका में कार्तिक की विशेषज्ञता इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में 250 से ज़्यादा मैचों में भाग लेने और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 180 इंटरनेशनल मैचों से आती है।

लंदन स्पिरिट के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट ने एक बयान में कहा, 'लंदन स्पिरिट में DK का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। वह हमारे खेल में सचमुच एक अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और शॉर्ट-फॉर्मेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा। उनके साथ काम करना भी बहुत मजेदार है और वह जो कुछ भी करते हैं उसमें एक जबरदस्त एनर्जी और उत्साह लाते हैं।' बोबट ने कहा, 'खेल में अहमियत रखने वाले एक और एलीट इंसान को साइन करना हमारे एम्बिशन और इस बात को दिखाता है कि हम अपने प्लेयर्स को सबसे अच्छा सपोर्ट देने को कितना महत्व देते हैं।'

इस बीच कार्तिक ने नया रोल लेने पर कहा, 'लंदन स्पिरिट में शामिल होने का यह कितना रोमांचक समय है! जब मैंने Mo, MCC और टेक टाइटन्स के प्लान्स और एम्बिशन्स के बारे में सुना, तो मैं सच में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित था। लॉर्ड्स में काम करते हुए इंग्लिश समर बिताना सच में एक सपने के सच होने जैसा है। यह वह ग्राउंड है जहां मैंने भारत के लिए डेब्यू किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, लॉर्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अगले साल स्क्वाड को एक साथ आते देखने और कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ काम करने का इंतजार नहीं कर सकता।' कार्तिक के लिए नया रोल काफी आसान होगा जिन्होंने IPL में RCB में बोबट और स्पिरिट के हेड कोच एंडी फ्लावर दोनों के साथ मिलकर काम किया है।

पाकिस्तान में भी छाये हैं अभिषेक, सबसे अधिक सर्च किये गये

लाहौर। भारतीय टीम के युवा आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के कारण पड़ौसी देश पाकिस्तान में भी छाये हैं। इसका अंदाजा इसी से होता है कि पाकिस्तान में 2025 में सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी को लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया है। वह बाबर आजम, शहीन अफरीदीद या हारिस रऊफ नहीं बल्कि अभिषेक हैं। यहां तक कि भारत के ही विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अभिषेक से पीछे रहे गये हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक को भारत से भी अधिक पाक में सर्च किया गया।

इसका कारण एशिया कप को माना जा रहा है जिसमें अभिषेक ने सेमीफाइनल तक विस्फोटक पारियां खेली थीं। एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम ने पाक को हराया था। एशिया कप में अभिषेक ने आक्रामक बल्लेबाजी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ लीग मुकाबलों में भी उन्होंने जमकर रन बनाये थे हालांकि फाइनल में वह शुरुआत में ही आउट हो गये थे। हैरानी की बात ये है कि सर्च किये गये शीर्ष दस खिलाड़ियों को बाबर और शाहीन का नाम नहीं है।

पाकिस्तान में 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए खिलाड़ियों की शीर्ष 10 की लिस्ट में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी जगह नहीं पा सके हैं।पाक में सबसे अधिक सर्च किये गये दूसरे खिलाड़ी हसन नवाज, तीसरे इरफान खान व चौथे साहिबजादा फरहान और पांचवें मुहम्मद अब्बास हैं। पाकिस्तान में सफलता के साथ-साथ भारत में भी अभिषेक ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा सर्च हुए। भारत की टॉप-10 सूची में ज्यादातर क्रिकेटर शामिल थे, जिसमें महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने भी अपनी जगह बनाई।

क्रिकेट जगत से आई बड़ी खबर: टीम चयन को लेकर नाराज 3 क्रिकेटरों ने कोच पर किया हिंसक हमला : सिर पर 20 टांके, कंधा टूटा

मुम्बई (एजेंसी)। पांडिचेरी क्रिकेट एसोसिएशन (CAP) इन दिनों विवादों की भेंट चढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार और खेल के अवसरों में अनियमितताओं की खबरों के बीच सोमवार को अंडर-19 टीम के हेड कोच एस. वेंकटरमन पर शॉकिंग हमला हुआ। जानकारी के अनुसार, तीन स्थानीय खिलाड़ी–सीनियर कार्तिकेयन जयसुंदरम, फर्स्ट-क्लास खिलाड़ी ए. अरविंदराज और एस. संतोष कुमारन–टीम चयन को लेकर नाराज थे और इसी गुस्से में कोच पर हमलावर हो गए।

सुबह करीब 11 बजे CAP की ट्रेनिंग फैसिलिटी में वेंकटरमन पर हमला किया गया। कोच ने बताया कि उन्हें नेट्स के पास घेर लिया गया और उनके सिर और कंधे पर हमला किया गया। सिर में गहरी चोट के कारण उन्हें 20 टांके लगाने पड़े और कंधे में फ्रैक्चर भी आया। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर आरोपी खिलाड़ियों की तलाश शुरू कर दी है। सब-इंस्पेक्टर एस. राजेश के अनुसार, कोच की हालत स्थिर है और फरार खिलाड़ियों को ट्रैक किया जा रहा है।

वेंकटरमन ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों ने उन्हें पकड़कर हमला किया और भारतीदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स फोरम के सेक्रेटरी जी. चंद्रन ने उन्हें भड़काया। उनका दावा है कि खिलाड़ियों ने उनसे मारपीट करने का कारण बताया कि उन्हें टीम में मौका तभी मिलेगा जब वे कोच को चोट पहुंचाएंगे। भारतीदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स फोरम ने कोच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वेंकटरमन ने अक्सर खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किया। फोरम के अध्यक्ष सेंथिल कुमारन ने कहा कि CAP में पिछले वर्षों में कई बार मुद्दों को BCCI के सामने उठाया गया है।

यह हमला इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के एक दिन बाद आया जिसमें CAP में खिलाड़ियों के चयन में गड़बड़ी और बाहरी खिलाड़ियों को स्थानीय दिखाने की शिकायतें सामने आईं। 2021 के बाद केवल पांच स्थानीय खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया।

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस मामले की गंभीरता से जांच करेगा। CAP के CEO राजू मेथा ने हालांकि दावा किया कि सभी नियमों का पालन किया गया है और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है।

आईपीएल नीलामी में इस बार पृथ्वी, सरफराज के नाम भी शामिल

मुम्बई (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी, जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार नीलामी में नहीं बिके बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को भी इसमें शामिल किया गया है।

इसके अलावा बल्लेबाज सरफराज खान को भी इसमें जगह मिली है। इन दोनों का ही बेस प्राइज 75 लाख रुपये है। शॉ ने 2018 से 2024 तक आईपीएल खेला था पर खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें पिछली बार किसी टीम ने नहीं खरीदा था। वहीं सरफराज को साल 2021 के बाद से ही निलामी सूची में शामिल नहीं किय गया था। वहीं कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज किए गए ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को भी नीलामी में जगह मिली है। उनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है। सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले कुणाल चंदेला और अशोक कुमार भी नीलामी की अंतिम सूची में शामिल हैं। नीलामी सूची में दो करोड़ बेस प्राइज में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जेक फ्रेजर मैकगर्क के अलावा न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर है।

बीसीसीआई ने मिनी नीलामी के लिए 9 खिलाड़ियों के नाम जोड़े, कुल 359 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीसी) ने 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली मिनी नीलामी के लिए जारी 350 खिलाड़ियों की सूची में 9 खिलाड़ियों को और शामिल किया है। इस प्रकार खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर अब 359 हो गयी है। सूची में जोड़े गये नामों में विराट कोहली के करीबी स्वस्तिक चिकारा शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रिलीज किया थ। वहीं एसोसिएट देश (मलेशिया) के विरनदीप सिंह को भी सूची में शामिल किया गया हैं। बचे हुए सात खिलाड़ी हैं त्रिपुरा के ऑलराउंडर मणिशंकर मुरासिंघ, चामा मिलिंद (हैदराबाद), के.एल. श्रीजित (कर्नाटक), इथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), राहुल राज नमाला (उत्तराखंड) और विराट सिंह (झारखंड). अंतिम नीलामी सूची में शामिल 359 खिलाड़ियों मे 247 भारतीय और 112 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से केवल 77 खिलाड़ियों को ही नया आईपीएल अनुबंध मिलेगा, इसमें 31 विदेशी खिलाड़ी हैं। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे अधिक 64.30 करोड़ रुपये, और उनके उसे 13 स्लॉट भरने हैं। हीं चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर है के पास 43.4 करोड़ रुपये हैं और उसे नौ स्लॉट भरने हैं।

आकाश चोपड़ा ने दी गंभीर को सलाह, सबसे लड़ाई न करें

नई दिल्ली (ईएमएस)। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा है कि वह पूरे जुनुन से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए कुछ मैचों में टीम की असफलता के कारण उनपर सवाल उठाने ठीक नहीं हैं। वहीं चोपड़ा ने गंभीर से भी कहा कि वह आलोचआओं को सकारात्मक लें और उनपर कठोर प्रतिक्रिया न दे। इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि कोच के तौर पर उनके अब तक के कार्यकाल में जरुरत से ज्यादा विवाद पैदा हुए हैं। ऐसे में मेरी सलाह है कि वह इतनी ज्यादा लड़ाइयां न मौल लें। हाल ही में गंभीर ने अगल–अलग कप्तान बनाने की सलाह देने वाले आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पर नाम लिए बिना ही निशाना साधा था और कहा था कि उन्हें अपनी सीमा में ही रहना चाहिये। चोपड़ा ने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी कर गंभीर अपनी परेशानियां ही बढ़ा रहे हैं। गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम पहले न्यूजीलैंड और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय मैचों की सीरीज के सभी मैच हारी थी जिसके बाद से ही गंभीर की कोचिंग पर लोगों ने सवाल उठाने शुरु कर दिये थे। चोपड़ा ने इसी को लेकर एक वीडियो में कहा, 'जब वह मीडिया के सामने आते है तो कुछ भी छुपाते नहीं हैं। दिल खोलकर बोलते हैं पर मेरी एक सलाह उन्हें है कि वह आलोचना पर भड़के नहीं और न किसी से लड़ाई मौल लें। साथ ही कहा कि जब आप अपने काम को लेकर इतने जोशीले होते हैं और किसी व्यक्ति या चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो कई लोग आपके असफल होने का इंतजार करने लगते हैं। कई बार लगता है कि आप अपने कामकाज के तरीके से इस तरह की आलोचना के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'गंभीर बेहद उत्साही व्यक्ति हैं। वह हमेशा देश और टीम के लिए पूरी ताकत झौंकने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा मानना है कि उन्हें किसी को खुश नहीं करना है। इसलिए वह लड़ाई न करते हुए अपना काम करते रहें।'

जूनियर महिला वर्ल्ड कप: आखिरी सेकंड में बराबरी, फिर शूटआउट में भारत ने उरुग्वे को हराया

सैंटियागो (चिली) (एजेंसी)। भारत ने आखिरी सेकंड में बराबरी करने के बाद उरुग्वे को ह्लद्ध हॉकी जूनियर महिला वर्ल्ड कप 2025 के 9/12 क्लासिफिकेशन मैच में 1-1 से ड्रॉ के बाद शूटआउट में 3-1 से हराया। भारत के लिए मनीषा ने (19वें) ने भारत के लिए गोल किया जिसके बाद जस्टिना अरेंगुई ने (60वें) मिनट सिर्फ दो सेकंड बाकी रहते पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला, जिससे सेंट्रो डेपोर्टिवो डे हॉकी सेस्पेड, एस्टाडियो नैशनल में मैच शूटआउट में चला गया।

भारत ने मैच की शुरुआत से ही गेंद पर कब्जा बनाए रखा, जल्दी दबाव बनाया और कई बार सकर्ल में एंट्री की। हालांकि, उरुग्वे को पांचवें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वे उसे भुना नहीं पाये। भारत ने 18वें मिनट में एक अच्छे पेनल्टी-कॉर्नर वेरिएशन के साथ जवाब दिया, लेकिन साक्षी राणा का शॉट ब्लॉक हो गया। अगले ही मिनट में मनीषा ने दूर से एक जोरदार गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ में भारतीयों ने 11 सकर्ल पेनिट्रेशन किए, जबकि उरुग्वे ने डिफेंसिव शेल में गहरी पकड़ बना ली थी।

ब्रेक के बाद भी यही पैटर्न जारी रहा भारत ने हाई लाइन बनाए रखी और उरुग्वे को पीछे धकेल दिया, लेकिन तीसरे क्वार्टर के बीच में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बावजूद वे बढ़त नहीं बना पाए। आखिरी क्वार्टर के 49वें मिनट में उरुग्वे ने आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन गोलकीपर निधि ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार बचाव करके भारत की बढ़त बनाए रखी। उरुग्वे ने आखिरी मिनटों में अपने गोलकीपर को हटाकर एक एक्स्ट्रा आउटफील्ड प्लेयर को शामिल किया, और यह कदम बहुत फायदेमंद रहा। दो सेकंड बाकी रहते, उन्हें एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे अरेंगुई ने शांति से गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया।

शूटआउट में भारत ने हिम्मत नहीं हारी। पूर्णिमा यादव, इशिका और कनिका सिवाच ने गोल किए, जबकि गोलकीपर निधि ने उरुग्वे को तीन बार गोल करने से रोका, जिससे 3-1 से जीत पक्की हो गई और भारत 9वें/10वें स्थान के प्लेऑफ में पहुंच गया। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को अपने आखिरी क्लासिफिकेशन मैच में स्पेन से होगा।

सभी प्रारुपों की कप्तानी शुभमन को दी जाये : गांगुली

कोलकाता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का कहना है कि बल्लेबाज शुभमन गिल को तीनों ही प्रारुपों में कप्तानी दी जानी चाहिये। गांगुली के अनुसार अभी शुभमन टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान हैं और भविष्य को देखते हुए उन्हें टी20 प्रारुप की भी कप्तानी दे देनी चाहिये। वहीं जहां कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने सभी प्रारुपों में अलग कप्तान बनाने को कहा है। वहीं गांगुली इससे सहमत नहीं हैं। गांगुली ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा 'मेरी नजर में शुभमन सभी प्रारुपों के लिए कप्तान होने चाहिए। वह पूरी तरह से कप्तानी संभालने में सक्षम है।' गांगुली ने इंग्लैंड दौरे का उदाहरण देते हुकहा, 'तीन महीने पहले इंग्लैंड में शुभमन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के नहीं होने के बाद भी एक युवा टीम की शानदार तरीके से कप्तानी कर सीरीज बराबरी पर समाप्त की थी। उस सीरीज में वह बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में ही सफल रहे थे।' गांगुली ने कहा कि उस सीरीज में शुभमन ने 750 से ज्यादा रन बनाए और चार शतक लगाये। विदेशी जमीन पर दबाव के बाद भी ऐसा प्रदर्शन करना असान नहीं होता। साथ ही कहा कि किसी भी खिलाड़ी को केवल कुछ असफलताओं के कारण कम नहीं समझना चाहिए। इस पूर्व कप्तान का मानना है कि नये कप्तानों को अपनी को साबित करने के लिए समय देना जरुरी है। प्रशंसकों और समीक्षकों को जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिये।ऋ कप्तान के तौर पर उन्हें पर्याप्त समय और समर्थन देना चाहिए। उनपर भरोसा रखना होगा तभी वह एक बेहतर कप्तान के तौर पर निखर सकेंगे।' गांगुली की इस बयान से साफ है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 टीम भले ही अच्छा कर रही हो पर उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए भविश्य के लिए शुभमन को तैयार किये जाने की जरुरत है।

लियोनेल मेस्सी को लगातार दूसरी बार चुने गए एमएलएस का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

फोर्ट लॉडरडेल (फ्लोरिडा)। इंटर मियामी के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेस्सी को मेजर लीग सॉकर (MLS) में लगातार दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अर्जेंटीना के इस 38 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन से उनकी टीम इंटर मियामी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार हासिल करने में सफल रही। MLS कप चैंपियन टीम के कप्तान मेस्सी एमएलएस के इतिहास में लगातार दो बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (एमवीपी) का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मंगलवार को उन्हें लीग के इस साल के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान का विजेता घोषित किया गया। मेस्सी ने अपने साथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके बिना यह पुरस्कार जीतना संभव नहीं था। वह लीग के इतिहास में दो बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनसे पहले प्रेकी ने 1997 और 2003 में यह पुरस्कार जीता था।

पीसीबी ने हैदर अली पर लगा प्रतिबंध हटाया, लगे थे बलात्कार के आरोप

कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बल्लेबाज हैदर अली पर लगा अस्थायी निलंबन हटा लिया है, जिन्होंने सितंबर में मैनचेस्टर में बलात्कार के आरोपों से बरी होने के बाद से किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। PCB ने बुधवार को पुष्टि की कि अली उन नौ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया है। बोर्ड के एक सूत्र ने बताया, 'खिलाड़ियों को 23 जनवरी तक इस प्रतियोगिता में खेलने की अनुमति दे दी गई है।' पाकिस्तान के लिए 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलने वाले अली तब पाकिस्तान शाहीन टीम (पाकिस्तान ए) के साथ इंग्लैंड दौरे पर थे जब ब्रिटेन में जन्मी एक पाकिस्तानी महिला ने मैनचेस्टर शहर की पुलिस में उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया। PCB ने जांच के नतीजे आने तक अली को निलंबित कर दिया था। मैनचेस्टर पुलिस ने 25 सितंबर को यह मामला बंद कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि उन्हें इस मामले को अदालत में भेजने या क्रिकेटर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। PCB ने मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, ख्वाजा नफे और एहसानाउल्लाह को भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए NOC जारी की है। पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज उमर अकमल को ह्लह्रष्ट देने से इनकार कर दिया गया है। अकमल ने इस पर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है।

टी20आई : पावरप्ले में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा, अर्शदीप सिंह बड़े खिलाड़ी की बराबरी कर नम्बर 1 पर आए

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले ओवर्स (1-6 ओवर) हमेशा से बल्लेबाजों का पसंदीदा समय माना जाता है, लेकिन भारत के तेज़ और स्पिन गेंदबाजों ने इस अवधि में लगातार विकेट लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक, पावरप्ले में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़ों की लिस्ट में अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। दोनों के नाम 47-47 विकेट दर्ज हैं। उनके पीछे जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज़ शामिल हैं, जिन्होंने शुरुआती ओवरों में मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई है। अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में भूवनेश्वर कुमार की बराबरी की है।

अर्शदीप सिंह ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड ‒ 47 विकेट के साथ नंबर 1 पर

भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20आई में पावरप्ले ओवर्स में सबसे ज़्यादा 47 विकेट लेकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। क्रिकेट जगत में अर्शदीप अपनी स्विंग, पेस वेरिएशन और शुरुआती ओवरों में घातक लाइन-लेंथ के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में अपनी पहचान बनाने वाले अर्शदीप ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी साबित कर दिया है कि वह भारत के लिए लंबे समय तक पावरप्ले स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। उनके शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता भारत को मजबूत शुरुआत देती है और विपक्षी टीम पर दबाव डालती है।

भुवनेश्वर कुमार की बराबरी की

अर्शदीप ने भुवनेश्वर कुमार की बराबरी की है जिनके नाम भी पावरप्ले में 47 विकेट दर्ज हैं। भुवी अपनी शानदार स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ के लिए शुरू से ही ञ्ज20द्ब क्रिकेट में सफल रहे हैं। भुवनेश्वर ने कई बड़े टूर्नामेंटों में पावरप्ले में अहम विकेट लेकर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। उनकी स्विंग गेंदबाज़ी खासकर नई गेंद से बेहद प्रभावशाली रही है, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक भारत का सबसे भरोसेमंद पावरप्ले गेंदबाज़ माना गया।

जसप्रीत बुमराह - 33 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर

दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज़ों में गिने जाने वाले जसप्रीत बुमराह पावरप्ले में 33 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बुमराह भले ही डेथ ओवर्स के राजा माने जाते हों, लेकिन शुरुआती ओवरों में भी वह उतने ही खतरनाक होते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, सीम मूवमेंट और अनोखी स्लोअर गेंदें बल्लेबाज़ों को भ्रमित करती हैं। बुमराह की मौजूदगी से भारत को हमेशा पावरप्ले में सफलता मिलने की उम्मीद रहती है।

अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर - स्पिनर्स की अहम भूमिका

पावरप्ले में स्पिनरों का इस्तेमाल जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने इसे गलत साबित किया है। दोनों के नाम 21-21 विकेट दर्ज हैं। अक्षर पटेल अपनी एक जैसी लाइन-लेंथ और तेज़ गति वाली गेंदों से बल्लेबाज़ों को टिकने नहीं देते। वाशिंगटन सुंदर शुरुआती ओवरों में स्पिन डालकर बल्लेबाज़ों को चौंकाते हैं और कई बार बड़े विकेट दिलाते हैं। इन दोनों स्पिनरों ने भारत की पावरप्ले रणनीति को और मजबूत किया है।

टी20आई क्रिकेट में 1-6 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

47 - अर्शदीप सिंह, 47 - भुवनेश्वर कुमार, 33 - जसप्रीत बुमराह, 21 - अक्षर पटेल, 21 - वाशिंगटन सुंदर

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

पवन ऊर्जा को लेकर ट्रंप के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक

न्यूयॉर्क , एजेंसी। अमेरिका के एक संघीय जज ने सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने वाले कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया। मैसाचुसेट्स डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज पैटी सारिस ने पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने वाले ट्रंप के 20 जनवरी के कार्यकारी ऑर्डर को खारिज कर दिया और इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया। जज ने कहा कि संघीय जमीन और पानी पर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट की लगभग सभी लीजिंग को रोकने का आदेश मनमाना है और यह अमेरिकी कानून का उल्लंघन है। सारिस ने न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिसिया जेम्स के नेतृत्व में 17 राज्यों और वाशिंगटन, डीसी के स्टेट अटॉर्नी जनरल के एक समूह की संयुक्त याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने ट्रंप के उस ऑर्डर को चुनौती दी थी जिसमें पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए लीजिंग और परमिट देने पर रोक लगा दी थी। ट्रंप अक्षय ऊर्जा के खिलाफ रहे हैं और बिजली बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं। मैसाचुसेट्स अटॉर्नी जनरल एंड्रिया जॉय कैंपबेल ने इस फ़ैसले को हरित नौकरियों और अक्षय ऊर्जा की जीत बताया।

फ्लोरिडा के गवर्नर ने मुस्लिम नागरिक अधिकार समूह को आतंकी संगठन घोषित किया

फ्लोरिडा , एजेंसी। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने सोमवार को अमेरिका के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार समूह को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। डेसेंटिस ने काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस और मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश दिया है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस और मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। यह आदेश फ्लोरिडा की एजेंसियों को निर्देश देता है कि वे दोनों समूहों और उन्हें सामान देने वालों को किसी स्टेट एग्जीक्यूटिव या कैबिनेट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट और फंड लेने से रोकें। वहीं ट्रम्प ने डेसेंटिस पर इसके लिए मुकदमा करने की बात कही है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना लगभग एक सदी पहले मिस्र में हुई थी और इसकी दुनिया भर में ब्रांच हैं। इसके नेताओं का कहना है कि इसने दशकों पहले हिंसा छोड़ दी थी और अब यह चुनावों और दूसरे शांतिपूर्ण तरीकों से इस्लामी राज स्थापित करना चाहता है। आलोचक, जिनमें पश्चिम एशिया इलाके की तानाशाह सरकारें भी शामिल हैं, इसे एक खतरा मानते हैं।

अफगानों पर पाकिस्तान के हमलों की निंदा

काबुल, एजेंसी। भारत ने पाकिस्तान की ओर से अफगान नागरिकों पर किए गए ताजा हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, हम सीमा पर हुई झड़पों की खबरों से अवगत हैं, जिनमें कई अफगान नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत, अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का दृढ़ता से समर्थन करता है। यह हमला दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम समझौते के दो महीने से भी कम समय बाद हुआ है।

संसद पुनर्स्थापना की मांग पर नेपाली कांग्रेस पहुंची शीर्ष कोर्ट

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में प्रतिनिधि सभा की पुनर्स्थापना की मांग पर नेपाली कांग्रेस (नेकां) भी सुप्रीम कोर्ट गई है। पार्टी के मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे ने बताया कि कांग्रेस ने वकील के जरिये पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्म खाती को इसी मांग पर सुप्रीम कोर्ट भेजा है। खाती कांग्रेस के निर्वाचन समिति संयोजक भी हैं। घिमिरे ने कहा, संसद पुनर्स्थापना की मांग हमारे लिए बेहद जरूरी है। इससे पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भी इसके लिए रिट याचिका दायर कर चुकी है।

पाकिस्तान : सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में छह आतंकी ढेर

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में छह आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। गोलीबारी में एक सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया और तीन घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन अफगानिस्तान की सीमा से सटे मोहमंद कबायली जिले के सोरन दर्रा इलाके में शुरू किया गया था। गोलीबारी थमने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया।

ट्रम्प बोले- भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा:सस्ता चावल भेज रहा

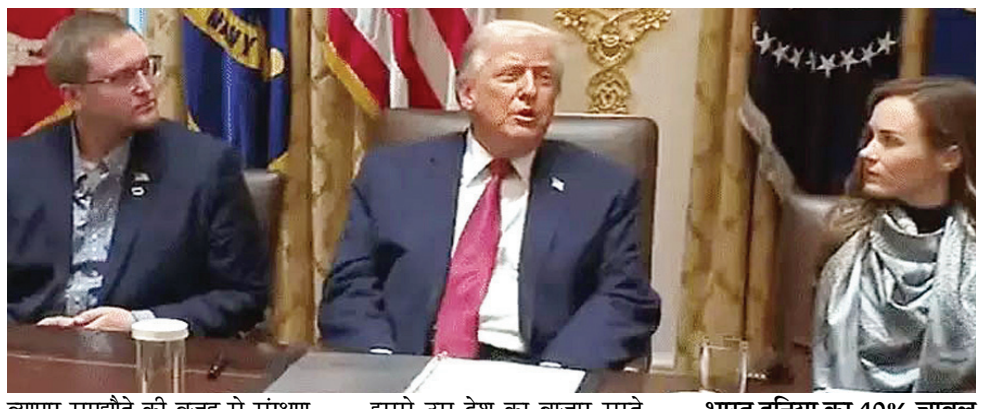

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रम्प ने यह बात सोमवार को व्हाइट हाउस में उस समय कही, जब वे किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। ट्रम्प ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहां के किसानों की कमाई कम हो रही है।

उन्होंने इसे 'डंपिंग' बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रम्प ने अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की छूट मिली हुई है। मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अभी बातचीत चल रही है।

कनाडाई फर्टिलाइजर पर भी टैरिफ लग सकता है : ट्रम्प ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका कनाडा से आने वाली खाद पर भी कड़े टैरिफ लगा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी खाद कनाडा से आती है। अगर यह बहुत सस्ती हो गई तो हम उस पर सख्त टैरिफ लगा देंगे। कनाडा ,अमेरिका को पोटाश खाद की सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। अब तक इसे व्यापार समझौते की वजह से संरक्षण मिला हुआ है।

अमेरिका में महंगाई और बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रम्प पर दबाव बढ़ रहा है। किसान भी बढ़ती लागत से परेशान हैं। अगर खाद पर नया टैरिफ लग गया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने हाल ही में पोटाश और फॉस्फेट को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल किया था, ताकि उनकी सप्लाई बनी रहे, लेकिन किसान अभी भी इसे लेकर परेशान हैं।

आसान भाषा में डंपिंग का मतलब जानिए : डंपिंग का मतलब है कि कोई देश अपनी चीजें दूसरे देश में बहुत ही कम दाम पर बेचता है। यह इतना कम होता है कि वहां की लोकल कंपनियां और किसान उस कीमत पर सामान बना ही नहीं पाते।

इससे उस देश का बाजार सस्ते विदेशी माल से भर जाता है और स्थानीय लोगों का कारोबार नुकसान में चला जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे लोकल मार्केट पर विदेशी कंपनियों या प्रोडक्ट का कब्जा हो जाता है। अगर ट्रम्प भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाला चावल काफी महंगा हो जाएगा। इससे वहां भारतीय चावल खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही भारत के उन किसानों और निर्यातकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो अपनी फसल का बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजते हैं। महंगा होने की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की मांग कम हो सकती है।

भारत दुनिया का 40% चावल एक्सपोर्ट करता है : भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। सस्ते घरेलू चावल और बड़े भंडार की वजह से भारत दुनिया भर में लगभग 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल चावल निर्यात लगभग 15 मिलियन टन तक पहुंच गया था। भारत मुख्य तौर पर दो तरह के चावल एक्सपोर्ट करता है बासमती और गैर-बासमती। 2023 में पश्चिम अफ्रीकी देश गैर-बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार थे, जबकि बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार मिडिल ईस्ट के देश सऊदी अरब, ईरान और इराक थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, 2023 में भारत ने अमेरिका को लगभग 281,873 टन चावल एक्सपोर्ट किया था।

पिछले पांच साल में बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़कर 42 फीसदी हुआ

ढाका, एजेंसी। नोबेल विजेता युनूस ने बड़े दमखम के साथ बांग्लादेश का नेतृत्व संभाला था। लेकिन फिलहाल उनके नेतृत्व में बांग्लादेश भी पाकिस्तान के कंगाली वाले रास्ते पर जाता दिखाई दे रहा है। पिछले पांच साल में बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश भी उन देशों की कतार में आ गया है, जो विदेशी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। इस बात की जानकारी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय कर्जों पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में हुई है। इसके मुताबिक पिछले पांच साल में बांग्लादेश के ऊपर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विदेशी कर्जों पर किस्त भुगतान, मूलधन और ब्याज दोनों पर दोगुना हो गया है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश पिछले कई साल से बाहरी कर्ज के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। सरकार ने विदेशी कर्ज की बदौलत बड़ी परियोजनाएं लागू की हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मेट्रो रेल, पावर प्लांट, हवाई अड्डा टर्मिनल, अंडरवाटर टनल और ऊंची एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं में से कई के ऋण की अदायगी पहले ही शुरू हो चुकी है, वहीं कई अन्य को जल्द ही भुगतान किया जाना है।

बढ़ते ऋण बोझ के बारे में पूछे जाने पर, वर्ल्ड बैंक के ढाका कार्यालय के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जाहिद हुसैन ने प्रोथम आलो को बताया कि विदेशी उधार और ऋण चुकाने का दबाव कोविड-19 काल से बढ़ रहा है। उन्होंने कहाकि हमारे विकास में जो साझेदार हैं, अब वो कड़ी शर्तें लगा रहे हैं। इनमें कम ग्रेस पीरियड, घटा हुआ मैच्योरिटी टाइम और उच्च ब्याज दरें शामिल हैं, और इसके परिणामस्वरूप, मूलधन और ब्याज भुगतान का बोझ महत्वपूर्ण और लगातार बढ़ रहा है।

जाहिद हुसैन ने आगे बताया कि विदेशी कर्ज से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहाकि पहले विश्व बैंक और आईएमएफ की ऋण स्थिरता रिपोर्टों में बांग्लादेश लो रिस्क कैटेगरी में था। लेकिन अब यह मध्यम श्रेणी में आ गया है।

लंदन: हीथ्रो हवाई अड्डे पर मिर्च स्प्रे हमले में ब्रिटेन पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां कीं

लंदन , एजेंसी। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर हुई घटना की जांच कर रही ब्रिटेन की पुलिस ने सोमवार को दो और गिरफ्तारियां कीं। इस घटना में सप्ताहांत में मिर्च स्प्रे के हमले में 21 लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि डकैती और हमले के संदेह में गिरफ्तार 24 वर्षीय व्यक्ति और डकैती की साजिश के संदेह में गिरफ्तार 23 वर्षीय महिला अभी भी हिरासत में हैं।

रविवार को घटनास्थल के निकट डकैती और हमले के संदेह में गिरफ्तार किए गए 31 वर्षीय व्यक्ति को 'जांच के तहत' छोड़ दिया गया है, जबकि पुलिस जांच जारी है। मेट पुलिस ने एक बयान में कहा, 'जांच शुरू की गई, जिसमें पता चला कि हमले से पहले, कार पार्क की लिफ्ट से बाहर निकलने पर दो महिलाओं के सूटकेस लूट लिए गए थे।' पुलिस ने बताया, 'लूट के दौरान, बदमाशों ने महिलाओं पर मिर्च स्प्रे जैसा कोई पदार्थ छिड़का। इस पदार्थ का असर आसपास के लोगों पर पड़ा और उन्हें मामूली चोटें आईं।' ये गिरफ़्तारियां पश्चिम लंदन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 बहुमंजिला पार्किंग में हुए हमले और डकैती के बाद हुईं। लंदन एम्बुलेंस सेवा ने 21 लोगों का इलाज किया, जिनमें से पांच को पास के अस्पताल ले जाया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई।

ऑस्ट्रेलिया में जंगल में लगी आग का कहर जारी 40 घर तबाह

केनबरा, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया में वन आग के कारण रविवार को दो प्रांतों के लगभग 40 घर तबाह हो गए और इसे काबू करने की कोशिश में एक दमकलकर्मी की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स के बुलादेला शहर के पास रविवार की रात आग बुझाते समय 59 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर पेड़ गिर गया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्रामीण अग्निशमन सेवा के प्रमुख कमिश्नर ट्रेंट कर्टिन ने बताया कि आग ने 3,500 हेक्टेयर जंगल को तबाह कर दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति एआई पर जारी करेंगे 'वन रूल' वाला ऑर्डर

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राज्य अलग-अलग कानून बनाकर टेक कंपनियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि इस सप्ताह वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए एक ही नियम (One Rule) वाला एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश जारी करने जा रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैं इस हफ्ते एआई के लिए एक नियम वाला कार्यकारी आदेश जारी करूंगा। अपनी पोस्ट में आगे उन्होंने कहा कि इस समय हम दुनिया के सभी देशों से काफी आगे हैं, लेकिन अगर हमारे 50 राज्य, जिनमें से कई में बहुत बुरे लोग बैठे हैं, अलग-अलग नियम बनाने और मंजूरी देने में लगे रहे, तो यह बढ़त ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई अपनी शुरुआती अवस्था में ही नष्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कदम ट्रंप का एआई नीति पर अपनी मजबूत छाप छोड़ने का ताजा प्रयास है। उनका स्पष्ट मानना है कि 50 अलग-अलग राज्य स्तर के नियमों का जाल अमेरिकी कंपनियों के लिए अनुपालन को असंभव बना देगा और नवाचार को मार डालेगा। तकनीकी उद्योग के बड़े नेता लंबे समय से राज्य-दर-राज्य विनियमन के खिलाफ बोलते रहे हैं। इस लिहाज से यह आदेश उनके लिए बड़ी जीत होगी। बता दें कि ट्रंप और टेक दिग्गजों ने बार-बार चेतावनी दी है कि अलग-अलग राज्य कानून नवाचार रोक देंगे और अनुपालन को बेहद जटिल बना देंगे। हालांकि, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और अर्कांसस की गवर्नर सारा हकाबी सैंडर्स सहित कई रिपब्लिकन गवर्नरों ने इस कदम की आलोचना की है। वे इसे राज्यों के अधिकारों पर हमला मानते हैं। माना जा रहा है कि किसी भी ऐसे कार्यकारी आदेश को तुरंत कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, वाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने सोमवार को सीएनबीसी को बताया कि उन्होंने इस आदेश का मसौदा देख लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य इन कंपनियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आने वाला कार्यकारी आदेश यह साफ कर देगा कि अमेरिका में अमेरिकी कंपनियों के लिए सिर्फ एक ही नियम होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने देखे गए संभावित आदेश के मसौदे में न्याय विभाग को उन राज्यों के खिलाफ मुकदमा करने की शक्ति दी जाएगी जिनके एआई कानून संघीय सरकार असंवैधानिक मानती है। साथ ही, जिन राज्यों के नियम बहुत सख्त या बोझिल होंगे, उन्हें संघीय फंडिंग में कटौती भी की जा सकेगी।

जापान में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप से 30 लोग घायल, अधिकारियों ने बड़े झटकों की चेतावनी दी

टोक्यो, एजेंसी। जापान में आए 7.5 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से 30 लोगों के घायल होने की खबर है। इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को दी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 11:15 पर आओमोरी प्रीफेक्चर के पूर्वी तट पर आया। भूकंप का केंद्र 54 किलोमीटर नीचे था। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने चेतावनी दी कि इस झटके के बाद आने वाले दिनों में उसी इलाके में इसी तरह या उससे भी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अगले एक-दो सप्ताह तक स्थानीय अधिकारियों और मौसम एजेंसी से अपडेट के लिए अलर्ट रहने और आने वाले भूकंप के लिए तैयार रहने को कहा है। स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में घर के जरूरी सामान को रखने को कहा गया है। एजेंसी के मुताबिक, भूकंप होक्काइडो और उत्तर-पूर्वी जापान के तटों से लगी एक खाई के पास आया। यह एक ऐसा जोन है जहां पैसिफिक प्लेट के होंशू मुख्य द्वीप के नीचे खिसकने से बड़े भूकंप आ सकते हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी ने बाद में भूकंप की तीव्रता को पहले के 7.6 के अनुमान से बदल दिया और झटके के बाद 3 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की। इवाते प्रीफेक्चर में सबसे ऊंची सुनामी लहरें 70 सेंटीमीटर तक पहुंच गईं। भूकंप के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद, सुनामी की चेतावनी जारी की गई जिसे मंगलवार सुबह 6:20 में हटा लिया गया। आओमोरी के कुछ हिस्सों में भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंपीय तीव्रता स्केल 7 पर 6 से ज्यादा दर्ज की गई। झटके के बाद, मौसम एजेंसी ने खाई के पास एक बड़े भूकंप के लिए एक खास अलर्ट जारी किया, जिसे 'ऑफ द कोस्ट ऑफ होक्काइडो एंड सैनरिकु सबसीक्वेंट अर्थक्वेक एडवाइजरी' के नाम से जाना जाता है, जो 7.0 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सक्रिय होता है।

पुतिन के बाद अब जेलेंस्की भारत आ सकते हैं : अगले महीने का प्लान

कीव/नई दिल्ली, एजेंसी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जेलेंस्की का यह पहला भारत दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने 1992, 2002 और 2012 में अब तक सिर्फ तीन बार भारत दौरा किया है। विक्टर यानुकोविच आखिरी यूक्रेनी राष्ट्रपति थे, जो 2012 में भारत आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, रूस और यूक्रेन बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। 2024 में भी भारत ने ऐसा ही किया था। पीएम मोदी पहले मॉस्को गए और पुतिन से मिले थे और कुछ ही हफ्तों बाद वे कीव जाकर जेलेंस्की से मिले थे। भारत और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच पिछले कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। यह बातचीत पुतिन की यात्रा से पहले ही शुरू हो गई थी।

जेलेंस्की का भारत दौरा कई फैक्टर पर निर्भर करेगा : रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेलेंस्की का दौरा कब और कैसे होगा यह कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि ट्रम्प की नई शांति योजना किस दिशा में जाती है, युद्ध की स्थिति कैसी रहती है और यूक्रेन की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि इस समय वहां जेलेंस्की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से दबाव में है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी, पुतिन और जेलेंस्की दोनों से लगातार बात करते रहे हैं। फोन कॉल हों या अंतरराष्ट्रीय बैठकें दोनों नेताओं के साथ उनका संपर्क बना रहा है।

पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया था : पीएम मोदी अगस्त 2024 में यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया था। बैठक में मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई थी। बाद में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मीडिया से कहा था कि भारत एक बड़ा देश है, उसका प्रभाव अधिक है। भारत पुतिन को रोक सकता है। भारत अपनी भूमिक निभाएगा।

चिंता जताने के बावजूद पाकिस्तान को पैसे देते जा रहा आईएमएफ, अब जारी किए 1.2 अरब डॉलर

इस्लामाबाद, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता और सुधारों में कमी पर चिंता जताने के बावजूद देश को 1.2 अरब डॉलर की नई किस्त जारी कर दी है। यह राशि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और महंगाई को नियंत्रित करने में सहायक होगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दीर्घकालिक सुधारों के बिना जोखिम भरा हो सकता है।

आईएमएफ ने सोमवार को पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की तीसरी किस्त जारी करने की घोषणा की। यह धनराशि उन दो कार्यक्रमों के तहत दी गई है, जिनका उद्देश्य देश में आर्थिक सुधारों को समर्थन देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। इस ताजा किस्त के साथ वाशिंगटन स्थित संस्था द्वारा इस्लामाबाद को अब तक कुल 3.3 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं। आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक नाइजल क्लार्क ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान द्वारा लागू किए गए सुधारों ने हालिया झटकों के बावजूद मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विशेष रूप से इस वर्ष की मॉनसून बाढ़ों का उल्लेख किया, जिनमें सितंबर तक 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा प्राथमिक राजकोषीय संतुलन लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता, साथ ही बाढ़ प्रभावितों को जरूरी आपात सहायता प्रदान करना, उनकी वित्तीय विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, आईएमएफ अधिकारी ने सरकार से आर्थिक डेटा कलेक्शन में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और निवेश को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख सुधारों की गति तेज करने का आग्रह भी किया।

गंभीर आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान : पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से लंबे आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी कर्ज पर भारी निर्भरता रखने वाला देश 2023 में डिफॉल्टर होने से बाल-बाल बचा। तब 2024 में आईएमएफ द्वारा 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी मिली थी। दक्षिण एशियाई यह देश अर्जेंटीना और यूक्रेन के बाद आईएमएफ का तीसरा सबसे बड़ा देनदार है। वित्तीय मोर्चे पर राहत पाने के लिए पाकिस्तान ने जनवरी 2024 में विश्व बैंक से 10 वर्षों के लिए 20 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज पर भी समझौता किया था। आईएमएफ की ताजा किश्त से पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने और सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक आर्थिक सुधारों को तेज़ी से लागू किए बिना स्थिति में स्थायी सुधार की संभावना अभी सीमित है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टोल प्लाजा पर सिख युवक से मारपीट और पगड़ी उछालने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र (एजेंसी)। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में टोल प्लाजा पर सिख युवक से मारपीट और उसकी उसकी पगड़ी उछालने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर लोगों ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया था। आरोपियों ने टोल ना देने पर युवक से मारपीट की थी, जबकि पीड़ित का कोई टोल नहीं लगता था। जानकारी के मुताबिक पिहोवा में सिख युवक के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों ने मारपीट की थी और पीड़ित की पगड़ी भी उछाल दी थी। बाद में गुस्साए सैकड़ों लोगों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया था। किसान जठेबंदियों ने अब इस मामले पर पुलिस का धन्यवाद किया था। टोल के मैनेजर ने किसानों के सामने आकर माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। साथ ही टोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी के गले में आईकार्ड होंगे। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने इस घटना में नरेश कुमार, अमन गिर, गुरदेव सिंह, सोहन सिंह उर्फ़ सोनी, रोबिन व ललित वासीयान गुजरां जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया है। बता दें 8 दिसंबर 2025 को गुमथलागढ़ पुलिस चौकी को दी अपनी शिकायत में नवनीत सिंह ने बताया कि वह गांव थाने का रहने वाला है और उसे गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा आता है। एनएचएआई के नियमों के मुताबिक टोल प्लाजा के क्षेत्र में आने के कारण उनके गांव का टोल नहीं लगता। 8 दिसंबर शाम वह अपने काम से कैथल जा रहा था कि प्लाजा पर टोल देने को लेकर टोल कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की उसे अपशब्द कहे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरु की थी।

महाराष्ट्र कांग्रेस को विधानसभा स्पीकर ने दिया झटका... महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की मांग खारिज

मुंबई(एजेंसी)। महाराष्ट्र कांग्रेस को बुधवार को एक बड़ा झटका लगा है, जहाँ विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की मांग को खारिज किया है। सीनियर कांग्रेस विधायक और पूर्व स्पीकर नाना पटोले ने स्पीकर से इसकी मांग की थी। कांग्रेस नेता पटोले ने हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में अराजकता और अनियमितताओं का आरोप लगाकर एसईसी पर दिन दहाड़े लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि मुख्यमंत्री (तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस) ने भी अनियमितताओं की अभूतपूर्व प्रकृति को स्वीकार किया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मांग को खारिज कर दिया। स्पीकर ने कहा कि पटोले की मांग राज्य विधानसभा के दायरे से बाहर थी और यह हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग से जुड़े हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं थी। एसईसी ने 24 नगर परिषदों और 76 नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के 154 वार्डों में मतदान शुरू होने से ठीक पहले स्थानीय निकाय चुनावों को 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिया था। सीएम फडणवीस ने भी स्थगन पर नाराज़गी व्यक्त की थी, यह कहते हुए कि चुनाव निर्धारित होने से एक दिन पहले स्थगन का कोई प्रावधान नहीं है। पार्टी ने स्थगन को एक सोची-समझी राजनीतिक चाल बताते हुए एसईसी की आलोचना की थी और कहा था कि महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अराजकता फैल गई है।

पीएम मोदी ईवीएम नहीं, लोगों के दिलों को करते हैं हैक : कंगना रनौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र के आठवें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जहां राज्यसभा में 'वंदे मातरम' को लेकर बहस छिड़ी रही, वहीं लोकसभा में चुनाव सुधार मुख्य मुद्दा बना रहा। इसी दौरान अभिनेत्री से भाजपा सांसद बनी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर विपक्ष में रहते हुए लगातार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। लोकसभा में अपनी टिप्पणी के दौरान कंगना रनौत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते, वे लोगों के दिलों को हैक करते हैं। यह प्रतिक्रिया उन्होंने उन विपक्षी आरोपों के जवाब में दी, जिनमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे थे। कंगना ने सदन में उस 'अंतरराष्ट्रीय महिला' की तस्वीर दिखाने पर भी कांग्रेस पर हमला बोला, जिसका प्रयोग राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की आलोचना के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि यह उस महिला का अपमान है और वे इसके लिए उससे माफी मांगती हैं। भाजपा सांसद ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष रोज हंगामा खड़ा कर समय बर्बाद कर रहा है, जिससे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रभावित हो रही है। कंगना ने कहा कि विपक्ष की इस रणनीति के कारण संसद का वातावरण लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है और जनहित के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं।

दिल्ली में फिर एक स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी... खालिस्तान आंदोलन का जिक्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को संस्कृति स्कूल को भी इसतरह का धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें खालिस्तान आंदोलन का जिक्र था। संदेश में लिखा था, आज दोपहर 12:05 बजे बम धमाका होगा? पुलिस अधिकारी धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं और स्कूलों को छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

बुधवार सुबह, स्कूलों ने एहतियात के तौर पर अभिभावकों को अपने बच्चों को लेने के लिए तुरंत सूचना दी। सूचना में छात्रों और अभिभावकों के बीच घबराहट पैदा किए बिना स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और संभालने के लिए छात्रों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल भेजने की प्रक्रिया बताई। स्कूल द्वारा जारी नोटिस में लिखा था, प्रिय अभिभावकगण, स्कूल को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है। एहतियात के तौर पर, स्कूल बच्चों को छुट्टी दे रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया नीचे दिए गए समय के अनुसार अपने बच्चे को लेने आ जाए।

महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके बुरे फंसे संत अनिरुद्धाचार्य; कोर्ट में परिवाद दर्ज, एक जनवरी को सुनवाई

मथुरा (एजेंसी)। वृंदावन के प्रसिद्ध संत और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके मुश्किलों में फंस गए हैं। उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा था, महिलाएं 25 वर्ष की उम्र में चार जगह मुंह मार लेती हैं। इसलिए उनकी शादी 14 वर्ष की आयु में हो जानी चाहिए। इस बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कोर्ट में शिकायत की थी। मथुरा सीजेएम कोर्ट ने परिवाद यानी शिकायत दर्ज करते हुए मामले में सुनवाई के लिए एक जनवरी 2026 की तारीख तय की है।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने मथुरा में मीडिया से बात की। भारतीय हिंदू महासभा आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने संत अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ न्यायालय में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें कहा गया था कि कथा प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करते हैं जो गलत है। संत ने एक प्रवचन के दौरान कहा था, महिलाएं 25 वर्ष की उम्र में चार जगह मुंह मार लेती हैं। इसलिए उनकी शादी 14 वर्ष की आयु में हो जानी चाहिए। विवादित बयान के बाद जनपद न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने मामला संज्ञान में लिया और 1 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी।

वृंदावन के प्रसिद्ध संत अनिरुद्धाचार्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर लाखों फॉलोअर हैं। अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर उनका गौरी गोपाल के नाम से आश्रम बना हुआ है। कुछ महीने पहले वृंदावन में कथा प्रवचन के दौरान शिष्यों ने पूछा लड़कियों की शादी कब हो जानी चाहिए। इस पर संत ने जवाब दिया कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष की अवस्था में हो जानी चाहिए। क्योंकि, 25 वर्ष की आयु होते-होते लड़कियां कई जगह मुंह मार लेती हैं जो गलत है।

अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने बताया मीरा राठौर के द्वारा सीजेएम कोर्ट में एक लिखित शिकायत की गई थी, उसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने वाद को पंजीकृत कर लिया है। अब अगली सुनवाई एक जनवरी 2026 को होगी। इस दिन शिकायतकर्ता मीरा राठौर अपने बयान दर्ज कराएंगी। मीरा राठौर ने कहा ऐसे संतो को जेल भेज देना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य विवादित टिप्पणी करते रहते हैं जो गलत है। मुझे नहीं लगता कि वह असली साधु संत हैं। साधु संतों की यह भाषा नहीं होती है। अगर यही बात कोई मौलाना मौलवी कहता तो उसके मकान-मस्जिद पर बुलडोजर चल जाता। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय में जीत हुई। हम मांग करते हैं मुकदमा दर्ज करके तत्काल अनिरुद्धाचार्य को जेल भेजना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य की भाषा बहुत गलत है।

राहुल गांधी जा रहे हैं जर्मनी यात्रा पर, बीजेपी ने बताया भारत बदनामी यात्रा

-विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की होने वाली जर्मनी यात्रा ने राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे भारत बदनामी यात्रा बताया है और कांग्रेस नेता पर विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी का विदेश यात्रा का फैसला एक बार फिर उनकी स्पष्ट प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राहुल 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे यूरोप भर के आईओसी नेताओं से मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि विपक्ष के नेता का मतलब पर्यटन का नेता होता है। वह एक गैर-गंभीर राजनेता हैं। लोग काम के मूड में हैं, जबकि वह छुट्टी के मूड में हैं। हमेशा के लिए छुट्टी के मूड में। उन्होंने कहा कि राहुलजी अक्सर विदेश चले जाते हैं, और याद दिलाया कि बिहार चुनावों में जब दूसरे लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब वे जंगल सफारी पर थे। जर्मनी यात्रा के पीछे के इरादे के बारे में पूनावाला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे किसी कारण से क्यों जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वे भारत के खिलाफ जहर उगलना चाहते हों। यह भारत बदनामी ब्रिगेड और भारत बदनामी टूर है। पूनावाला ने कहा कि विदेश नायक एक बार फिर वही कर रहे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं। विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। संसद 19 दिसंबर तक है, लेकिन खबरों के मुताबिक राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे।

महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता: गढ़चिरौली में 11 माओवादी कैडरों का आत्मसमर्पण

नागपुर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहाँ प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के 11 सीनियर और हार्डकोर कैडरों ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

आत्मसमर्पण करने वालों में कुल 11 कैडर शामिल है। इसमें दो डिवीजनल कमेटी सदस्य, तीन प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य, दो एरिया कमेटी सदस्य, चार आम पार्टी सदस्य शामिल है। इन सभी पर मिलाकर 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतना ही नहीं चार कैडरों ने अपनी वर्दी और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण में सबसे बड़ा नाम रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू गुड्डी लेकामी (57 वर्ष), जो भामरागढ़ एरिया का डिवीजनल कमेटी सदस्य था। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर जिले में महिलाओं ने भी आत्मसमर्पण किया है। यह इस साल का सबसे बड़ा सरेंडर नहीं है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। बात दें कि साल 2025 में अब तक गढ़चिरौली में 112 हथियारबंद माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। अक्टूबर 2025 में पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फभूपति उर्फसोनू सहित 61 बड़े कैडर ने आत्मसमर्पण किया था। 2005 से अब तक गढ़चिरौली पुलिस के सामने कुल 783 सक्रिय माओवादी हथियार डाल चुके हैं। डीजीपी शुक्ला ने बचे हुए माओवादियों से हथियार छोड़कर सम्मान की जिंदगी जीने की अपील की। माओवादी विचारधारा खोखली साबित हो चुकी है और आम आदिवासी उसकी हिंसा से तंग आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति उनके लिए अवसर प्रदान करती है। डीजीपी ने सी-60 कमांडो और अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अक्टूबर में लाहेरी जंगल में भूपति सहित 61 माओवादियों का सरेंडर करवाया था। गढ़चिरौली पुलिस ने प्रोजेक्ट उड़ान - विकास की एक झलक' नामक एक खास गाइडबुक जारी की। इसका उद्देश्य दूरदराज के आदिवासी इलाकों में चल रही सरकारी योजनाओं की आसान जानकारी देना है। डीजीपी ने कहा कि अब पुलिस सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास का माध्यम भी बनेगी।

सांसद गोगोई ने कसा तंज बोले- इंडिगो के पीछे की कहानी का पर्दाफाश होना चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिगो मामले को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल मंत्री के बयान दे देने से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे प्रकरण की असल कहानी सामने आनी चाहिए और सदन में विस्तार से चर्चा होना बेहद जरूरी है।

गौरव गोगोई ने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि पिछले दो दिनों में सरकार ने संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयानों में पूरी जिम्मेदारी एक निजी कंपनी पर डाल दी है, जैसे उसकी खुद की कोई भूमिका ही न हो। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो नियामक संस्थाओं की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बची। हजारों उड़ानें रद्द हुईं, यात्रियों को एयरपोर्ट पर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से दूर खड़ी दिखाई देती है।

सांसद ने यह भी कहा कि पायलटों की सुविधा के लिए लाए गए नए नियमों को सरकार ने अचानक वापस ले लिया। न पायलटों को राहत मिली, न यात्रियों को और न ही सरकार ने अपनी भूमिका स्वीकार की।

सिर्फ एक नोटिस जारी कर देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि लोकसभा में मंत्री का बयान आने के बाद विपक्ष ने असहमति जताते हुए वॉकआउट किया, क्योंकि सरकार पूरे मामले पर ईमानदार चर्चा से बच रही है। उनका कहना था कि एक सप्ताह में कितनी उड़ानें रद्द हुईं, यह केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। गोगोई ने एविएशन इंडस्ट्री की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही तेज़ी से बढ़ते एविएशन बाजार की बात करे, लेकिन इसका क्या लाभ जब एयरपोर्ट पर बुनियादी सुविधाएं महंगी हों, टिकटों के दाम आसमान छू रहे हों, पायलटों और ग्राउंड स्टाफ की स्थितियां खराब होती जा रही हों और पूरी इंडस्ट्री कुछ निजी कंपनियों के इशारों पर चल रही हो। इसी मुद्दे पर दूसरी सांसद फौजिया खान ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नोटिस भेजना जरूरी है, लेकिन क्या सारी गलती सिर्फ इंडिगो की है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उन्होंने सवाल किया कि जो नियम लागू किए गए थे, वे क्या सही थे और यदि नहीं, तो अचानक पूरी व्यवस्था कैसे ठप हो गई? वापस लिए गए नियमों की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए।

वंदे मातरम से जुड़े एक अन्य विवाद पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे जो भी कहा जाए, उससे सच्चाई नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि इतिहास स्पष्ट बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने क्या भूमिका निभाई और आज इस विषय पर सवाल उठाने वालों का उस दौर में कोई अस्तित्व तक नहीं था।

सोनिया गांधी को नोटिस जारी किए जाने पर कांग्रेस नेता किरण कुमार चमाला ने कहा कि बार-बार सोनिया गांधी और उनके परिवार को निशाना बनाना राजनीतिक विद्वेष का संकेत है। उन्होंने बताया कि चुनाव सुधारों पर चर्चा दो सत्रों की मांग के बाद शुरू हो सकी। उनके अनुसार कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि इसके प्रावधान सीमित हैं और इसे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही लागू किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल एविएशन सेक्टर की खामियों को उजागर किया है, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है। सरकार की जवाबदेही और नियामक संस्थाओं की भूमिका पर उठे सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं।

हुमायू का दावा: अगले साल मैं ही बनूंगा किंगमेकर, मेरे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस से हाल ही में निलंबित हुए मुरशिदाबाद के प्रभावशाली नेता एवं विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को बड़ा दावा किया कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वह किंगमेकर बनकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रस्तावित नई पार्टी के समर्थन के बिना राज्य में कोई भी सरकार बनाना असंभव होगा। कबीर ने संवाददाताओं से कहा, 2026 में न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल कर पाएगी। 294 सीटों वाली विधानसभा में कोई भी दल 148 का आंकड़ा नहीं छू सकेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद मैं किंगमेकर बनूंगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसे मेरे विधायकों का समर्थन लेना पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि उनकी नई पार्टी कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इतनी सीटें जीतेगी कि सरकार बनाने या गिराने की स्थिति में रहेगी। नई पार्टी की औपचारिक घोषणा 22 दिसंबर को होगी। पार्टी का नाम पूछे जाने पर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, '22 दिसंबर के बाद सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने कबीर के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के प्रदेश महासचिव अरूप चक्रवर्ती ने कहा, 'हुमायूं कबीर दिवास्वप्न देख रहे हैं। सरकार बनाने की बात करने से पहले उन्हें अपनी जमानत बचाने की चिंता करनी चाहिए। ऐसे निराधार दावे उनकी राजनीतिक हताशा को ही दर्शाते हैं।

इस बीच, हुमायूं कबीर के करीबियों ने दावा किया कि मुरशिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद शैली की नई मस्जिद के लिए अब तक लगभग तीन करोड़ रुपये का चंदा इकट्ठा हो चुका है। उनके अनुसार, मस्जिद परिसर में रखी 12 दान पेटियों से 57 लाख रुपये नकद मिले हैं, जबकि क्यूआर कोड के जरिए 2.47 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। चंदा लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कबीर का नई पार्टी के जरिए मुर्शिदाबाद और आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत आधार बनाने की तैयारी में हैं। उनके इस दावे ने 2026 के चुनावी समीकरण को और रोचक बना दिया है।

2027 में होंगे पंजाब विधानसभा चुनाव... लेकिन कांग्रेस के अंदर की खींचतान आने लगी सामने

-नवजोत कौर सिद्धू के 500 करोड़ वाले बयान से राज्य में मचा घमासान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी। यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के कारण की गई। दरअसल नवजोत कौर सिद्धू ने यह कहकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल पर आरोप लगाया कि तरनतारन उपचुनाव के उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज ने पार्टी टिकट के लिए दो कांग्रेस नेताओं को 10 करोड़ रुपये दिए, लेकिन बुर्ज ने इन आरोपों को निराधार बताया। निलंबन के बाद, नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर हमला बोला। उन्होंने वडिंग को एक असंवेदनशील और गैरजिम्मेदार, नैतिक रूप से बेईमान और भ्रष्ट अध्यक्ष बताया और उन्हें अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष वडिंग ने कहा कि कौर को निराधार आरोप लगाने और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के कारण निलंबित किया गया है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनके पति, नवजोत सिंह सिद्धू, सक्रिय राजनीति में तभी लौटने वाले हैं, जब कांग्रेस उन्हें पंजाब में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास किसी पार्टी को देने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं, लेकिन सिद्धू पंजाब को एक स्वर्णिम राज्य में बदल सकते हैं।

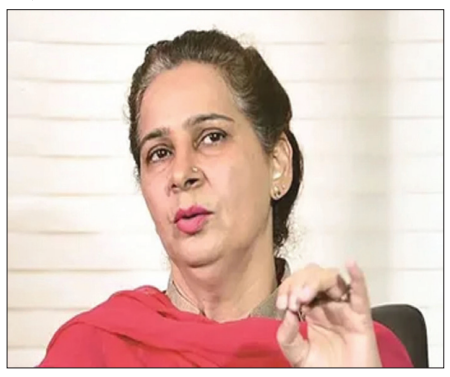

बात दें कि 2022 के पिछले चुनाव से कुछ महीने पहले भी पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बड़ी अंदरूनी खटपट सामने आई थी। इस आंतरिक कलह के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी (आप) के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम और सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाया था। बाद में वडिंग ने अध्यक्ष पद संभाला। यह घटनाक्रम दिखाता है कि पंजाब में 2027 के चुनावों से पहले कांग्रेस में गुटबाजी और नेतृत्व की लड़ाई फिर से खुले तौर पर सामने आ गई है।

इंडिगो एयरलाइंस के संकट से सिर्फ दिल्ली को 1000 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान

-कई सारे होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स और रिसोर्ट की हजारों बुकिंग रद्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिगो एयरलाइंस के संकट और फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण दिल्ली के कारोबारियों और पर्यटन क्षेत्र का बड़ा नुकसान हुआ है। इस बारे में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, इंडिगो संकट के कारण सिर्फ दिल्ली के व्यापार, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों को अब तक करीब 1000 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हो चुका है। बीते 10 दिनों में दिल्ली में यात्रियों/ लोगों (फुटफॉल) की संख्या में 25 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। दिल्ली के कई सारे होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स और रिसोर्ट की हजारों बुकिंग रद्द हो चुकी हैं। वहीं प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में लगी बड़ी प्रदर्शनियों (जैसे आटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल) में अनुमान के मुताबिक फुटफॉल नहीं दिखा, क्योंकि हजारों व्यापारी और पर्यटक फ्लाइट रद्द होने के कारण दिल्ली नहीं पहुँच सके है। बात दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना यात्रा करने वाले लगभग 50,000 व्यापारियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है, जिससे दिल्ली के बाजारों का व्यापार प्रभावित हुआ है।

वहीं बीते आठ दिनों से इंडिगो का संचालन पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं आ सका है। संकट शुरू होने से अब तक 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। यह समय (दिसंबर-जनवरी मध्य तक) दिल्ली में पर्यटन का मुख्य मौसम होता है, लेकिन संकट से क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग पर भी असर पड़ा है। पर्यटकों के होटल, टूरिस्ट व्हीकल, टूरिस्ट गाइड, रेस्टोरेंट की बुकिंग के साथ-साथ डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे आयोजनों को भी भारी नुकसान हुआ है, जहाँ मेहमान और कुछ मामलों में दूल्हा-दुल्हन के परिवार वाले भी नहीं पहुँच पाए। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है, और संकट शुरू होने से अब तक यह 12 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है। कंपनी का मार्केट कैपिटल (बाजार पूंजीकरण) भी 40,000 करोड़ रुपये के आस-पास कम हो गया है।

पर्यटन और व्यापार पर असर

दिल्ली में यह संकट उस समय आया है जब टूरिज्म का मौसम (जनवरी के मध्य तक) चल रहा है। बाजार जानकार के अनुसार, इंडिगो संकट के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग पर असर पड़ा है। वहीं एक अन्य कारोबारी ने बताया कि दिल्ली के व्यापार को 1000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। पर्यटकों के होटल, टूरिस्ट व्हीकल, टूरिस्ट गाइड, और रेस्टोरेंट की पहले से हुई बुकिंग कैंसिल हो गई है। डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे आयोजनों को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि मेहमानों के साथ-साथ कुछ मामलों में दूल्हा-दुल्हन के परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाए।